

आज

बेबाक

एक सर्वे के मुताबिक 55 प्रतिशत भारतीय रिश्वत देकर ही अपना काम करा पाते हैं। इसका मलबत यह है कि न खाऊंगा न खाने दूंगा वाली बात एक जुमला ही है। हकीकतन खाओ और खाने दो वाली नीति का पालन हो रहा है। सरकार चाहे किसी की भी हो उसके कर्णधार हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे वाली प्राचीन परंपरा का ही पालन करते हैं। भ्रष्टाचार रूपी कैसर का कोई उपचार नहीं है। बेहतर होगा कि सरकार तत्काल प्रभाव से भ्रष्टाचार को राष्ट्रीय शिष्टाचार घोषित कर दे और हर सरकारी दफ्तर में शिष्टाचार अनिवार्य कर रेट लिस्ट टंगा दे।

खास खबर

जोगी की जाति के मामले में सुनवाई 16 दिसम्बर को

बिलासपुर (नवप्रदेश)। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की जाति के मामले में हाई पावर कमेटी से लिखित में सारे दस्तावेज पेश करने के बारे में जानकारी देने को कहा है। श्री जोगी की याचिका पर सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति आर सी एस सामंत ने आज इस मामले में श्री जोगी के अधिवका राहुल त्यागी की इस आपत्ति के बाद यह आदेश दिया कि हाई पावर कमेटी के पूरे रिकार्ड उन्हें नहीं दिए गए हैं। रिपोर्ट से कई चीजे गायब हैं। इस दौरान त्यागी एवं महाधिवका सतीश चन्द्र मिश्रा के बीच जोरदार नोकझोंक और कहासुनी भी हुई। अदालत ने कहा कि सोमवार तक सरकार पुनः सोच समझ कर लिखित में अदालत को बताए कि उसने सभी रिकार्ड प्रस्तुत किए हैं यह नहीं। मामले में अगली सुनवाई 16 दिसम्बर को होगी।

कश्मीर में सब नॉर्मल लेकिन मैं कांग्रेस की स्थिति नॉर्मल नहीं कर सकता: शाह

नई दिल्ली ए.। लोकसभा में मंगलवार को गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस को राजनीतिक नेताओं से ज्यादा आम आदमी की चिंता करने की नसीहत देते हुए कहा कि नेताओं को हिरासत से छोड़ने का निर्णय स्थानीय प्रशासन की ओर से लिया जाएगा। लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के पूरक प्रश्न के उत्तर में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, 'जम्मू-कश्मीर में हिरासत में लिए गए नेताओं को छोड़ने का निर्णय स्थानीय प्रशासन की ओर से लिया जाएगा तथा वहां के मामले में केंद्र सरकार दखल नहीं देगी। उन्होंने कहा जब भी स्थानीय प्रशासन तय करेगी, उन्हें रिहा कर दिया जाएगा।'



फांसी का तख्त तैयार, 100 किलो की डमी के साथ हुआ ट्रायल

9 फरवरी, 2013 को जब संसद हमले के दोषी आतंकवादी अफज़ल को फांसी पर लटकाया गया था। तब उससे पहले भी उसके वजन की डमी को फांसी देकर ट्रायल किया गया था। उस ट्रायल में रस्सी टूट गई थी। इस बार मामला चार कैदियों का है। इसी वजह से जेल प्रशासन फांसी देते वक्त कोई चांस नहीं लेना चाहता।

नई दिल्ली ए.। तिहाड़ जेल में बंद निर्भया गैंगरेप के चारों दोषियों को फांसी पर लटकाने वाले मामले में अभी तक तिहाड़ जेल प्रशासन के पास कोई अंतिम लेटर नहीं आया है। लेकिन इससे पहले जेल प्रशासन ने अपनी तैयारियों का जायजा लेना शुरू कर दिया है। इसके तहत अगर इन चारों को फांसी दी जाती है तो इनमें से अधिकतम वजन वाले कैदी के वजन के हिसाब से एक डमी को फांसी देकर देखा गया। डमी में 100 किलो बालू-रेत भरी गई थी। डमी को एक घंटे तक फांसी के तख्ते पर लटकाए रखा गया। इसके पीछे

का मकसद यह देखना था कि अगर दोषियों को फांसी दी जाती है तो क्या फांसी देने वाले वह स्पेशल रस्सी इनके वजन से टूट तो नहीं जाएगी। तिहाड़ जेल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि ऐसा नहीं है कि फांसी देने के लिए सारी रस्सी बक्सर से ही मंगाई जाएगी। हमारे पास पांच रस्सी अभी भी हैं। लेकिन हम बक्सर प्रशासन से संपर्क कर रहे हैं। वहां शेष पृष्ठ 7 पर



जेल नंबर-3 में ही है फांसी का तख्त

इन दिनों तिहाड़ जेल में हर ओर निर्भया के दोषियों को ही फांसी पर लटकाने की बातें होती रहती हैं। इससे यह भी अब डरने लगे हैं। जब पवन को मंडोली से तिहाड़ जेल में शिफ्ट किया गया था। एक बार को उसे लगा था कि यह उसकी आखिरी रात है। जेल प्रशासन का कहना है कि रोहिणी, मंडोली और तिहाड़ में से तिहाड़ की जेल नंबर-3 में ही फांसी का तख्ता है।

निर्भया के दोषी की सुको में पुनर्विचार याचिका, कहा- यहां तो हवा से मर रहे, फिर फांसी क्यों

दिल्ली की निर्भया से गैंगरेप और जघन्य हत्या के दोषी अक्षय सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल कर अजीबोगरीब तर्क देते हुए सजा-ए-मौत से राहत की मांग की है। अक्षय ने अपनी याचिका में कहा कि दिल्ली की हवा और पानी में वैसे ही इतना प्रदूषण है कि लोग ज्यादा नहीं जी पा रहे हैं, फिर मौत की सजा की क्या जरूरत है? अक्षय ने हायास्पद तर्क देते हुए कहा, 'ऐसे बहुत कम लोग हैं, जो 80 से 90 साल की आयु तक पहुंच पा रहे हों।'

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने वेस्ले ग्रुप को सौंपा स्वीकृति-पत्र

सांची के पास निनोद में बनेगा 220 करोड़ का प्रदेश का पहला विश्व-स्तरीय गोल्फ कोर्स

नवप्रदेश संवाददाता

भोपाल। मध्यप्रदेश में निवेश के लिए तैयार किए गए वातावरण के परिणाम आने शुरू हो गए हैं। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची के पास ग्राम निनोद में 220 करोड़ रुपये लागत से 27 होल का विश्व-स्तरीय गोल्फ कोर्स सह-रिसॉर्ट एवं होटल बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री कमल नाथ ने मंत्रालय में वेस्ले ग्रुप के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डेरियन मुलेन्स को स्वीकृति पत्र (लेटर ऑफ अवार्ड) सौंपा। इस अवसर पर सचिव पर्यटन फैज अहमद किदवाई उपस्थित थे। मुख्यमंत्री कमल नाथ से वेस्ले ग्रुप के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में



निवेश के नए अवसर के लिए सरकार अपनी नीतियों को उदार बनाने के साथ ही रोजगार प्रधान निवेश को प्रोत्साहित करेगी। मध्यप्रदेश में पर्यटन के क्षेत्र में

निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए पर्यटन नीति (2016) को संशोधित कर 2019 में अल्ट्रा मेगा परियोजना का प्रावधान जोड़ा गया है। इसके परिणाम स्वरूप ही

वेस्ले ग्रुप ने निनोद गाँव में 70.718 हेक्टेयर में विश्व-स्तरीय गोल्फ कोर्स, होटल रिसॉर्ट एवं कन्वेंशन सेंटर एवं हेलीपैड के निर्माण का प्रस्ताव दिया था।

310 लोगों को मिलेगा रोजगार

मुख्यमंत्री कमल नाथ ने वेस्ले ग्रुप के प्रस्ताव को स्वीकृत कर लेटर ऑफ अवार्ड वेस्ले ग्रुप को सौंपा है। इस परियोजना से 310 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त होगा। पर्यटन नीति के प्रावधानों के अनुरूप इसमें से 247 पदों पर मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को नियुक्ति दी जाएगी। इस अवसर पर कपली के पार्टनर सीईओ वेस्ले ग्रुप गुर्बई श्री आलोक तिवारी, तक्रहुस खान तथा पर्यटन एवं मध्यप्रदेश पर्यटन बोर्ड के संयुक्त संचालक सुरेश झाहिया उपस्थित थे।

सरकारी कर्मचारियों को 10 लाख का स्वास्थ्य बीमा देने की तैयारी में मध्य प्रदेश सरकार

मध्य प्रदेश सरकार राज्य के कर्मचारियों को 10 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा देने की योजना बना रही है। इस योजना से राज्य से लगभग 12.5 लाख कर्मचारियों और उनके परिवारों को फायदा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

नवप्रदेश संवाददाता

भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार अपने कर्मचारियों को स्वास्थ्य बीमा योजना की एक बड़ी सौगात देने जा रही है। इस योजना में कर्मचारियों को 10 लाख रुपये तक के इलाज की सुविधा होगी। इस योजना का लाभ 12.5 लाख सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मिलने की संभावना है। राज्य की कमलनाथ सरकार कर्मचारी, युवा और किसानों के लिए कई योजनाओं को अमली जामा पहनाने में लगी हुई है। इसी के तहत सविदा कर्मचारियों को नियमित किया जा रहा है, अध्यापकों का शिक्षा विभाग में शामिल किया गया है और

अब स्वास्थ्य बीमा योजना को अस्तित्व में लाने की तैयारी है। सरकारी सूत्रों के अनुसार, प्रस्तावित योजना से लगभग 7.5 लाख सेवारत और लगभग पांच लाख सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों और उनके परिवारों को सामान्य रूप से पांच लाख रुपये तक और गंभीर बीमारियों में 10 लाख रुपये तक कैंशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। सूत्रों के अनुसार, विभिन्न निगम-मंडलों सहित सविदा पर कार्य कर रहे कर्मचारियों को भी इस योजना का लाभ दिए जाने पर विचार किया जा रहा है। बीमा की प्रीमियम राशि का निर्धारण सेवारत शासकीय सेवक के पे बैंड के अनुसार और सेवानिवृत्त शासकीय सेवक की पेंशन राशि के अनुसार होगा। मासिक प्रीमियम अंशदान राशि न्यूनतम 250 रुपये और अधिकतम 1000 रुपये होगी, जो शासकीय सेवक के वेतन से कटेगी। सामान्य शाश्वत सत्य को सिर्फ स्वीकार ही नहीं 'प्रस्तावित योजना में प्रत्येक सेवारत और सेवानिवृत्त शासकीय सेवक को हेल्थ कार्ड जारी किया जाएगा।

नागरिकता संशोधन बिल पर पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा

भारतीय संविधान पर हमला : राहुल गांधी

नई दिल्ली ए.। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि यह बिल भारतीय संविधान पर हमला है। अगर कोई इसका सपोर्ट कर रहा है तो वह हमारे देश की बुनियाद को नष्ट करने की कोशिश कर रहा है। बता दें कि सोमवार को लगभग 12 घंटे

तक चली बहस के बाद यह बिल लोकसभा में पास हो गया है। अब इसे राज्यसभा में रखने की तैयारी है। राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस की महासचिव प्रियंका



गांधी ने भी ट्वीट विरोध जताया। प्रियंका गांधी ने अपने ट्वीट में कहा कि बीती रात लोकसभा में नागरिकता संशोधन बिल पारित होने के साथ भारत कट्टरता और संकीर्ण सोच

वाले अलगाव से भारत के वादे की पुष्टि हुई है। उन्होंने कहा कि हमारा संविधान, हमारी नागरिकता एक मजबूत और एकजुट भारत के हमारे सपने से हम सभी से जुड़े हुए हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि सरकार के उस एजेंडे के शेष पृष्ठ 7 पर

किसानों को ऋण-मुक्त कर समृद्ध बनाने के लिए हुए क्रांतिकारी फैसले

नवप्रदेश संवाददाता

भोपाल। प्रदेश की कृषि प्रधान अर्थ-व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिये जरूरी है कि किसान चिन्ता-मुक्त हो, उसके पास आमदनी के स्थाई इंतजाम हो और उसे समय पर आवश्यक वित्तीय सहयोग भी मिले। राज्य सरकार ने इस शाश्वत सत्य को सिर्फ स्वीकार ही नहीं किया है बल्कि अपने प्रारंभिक अल्प-काल में ही इस दिशा में क्रांतिकारी फैसले लिये हैं और उन्हे जमीनी स्तर पर लागू भी

किया है। सरकार ने अपने वचन-पत्र में किसान कल्याण और कृषि विकास के मुद्दों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। सरकार ने सत्ता संभालते ही किसानों को पीढ़ियों के कर्जों से मुक्ति दिलाई है। साथ ही यह ऋम तब तक जारी रखने का संकल्प भी लिया है, जब तक प्रत्येक पात्र किसान कर्ज-मुक्त नहीं हो जाता। किसान को फसल बोने से लेकर फसल बेचने तक के काम में राज्य सरकार मदद कर रही है। बिजली, पानी आदि भी किसानों को रियायती दरों पर दिया जा रहा है।

आरबीआई ने एसबीआई का 12 हजार करोड़ का पकड़ा अंतर

नई दिल्ली ए.। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक के बीते वित्त वर्ष के फंसे कर्ज (एनपीए) में करीब 12,000 करोड़ रुपये का अंतर पाया गया है। एसबीआई ने शेयर बाजारों को भेजी सूचना में कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए गए आकलन के अनुसार, बीते वित्त वर्ष में एसबीआई का सकल एनपीए 1,84,682 करोड़ रुपये था। यह बैंक द्वारा दिखाए गए 1,72,750 करोड़ रुपये के

सकल एनपीए से 11,932 करोड़ रुपये अधिक है।

तो अनुमानित घाटा 6,968 करोड़ रुपये होता

इसी तरह बैंक का शुद्ध एनपीए 77,827 करोड़ रुपये था, वहीं एसबीआई ने 65,895 करोड़ रुपये का शुद्ध एनपीए दिखाया था। इस तरह शुद्ध एनपीए में भी 11,932 करोड़ रुपये का अंतर था।

सियासत मध्यप्रदेश में यूरिया संकट से अराजकता के हालात

यूरिया संकट , फिर राजनीति सड़कों पर !

मध्य प्रदेश में यूरिया संकट विकराल हो चुका है. सरकार कहती है कि केंद्र से सहयोग नहीं मिल रहा, जबकि बीजेपी कहती है कि ये सब कालाबाजारी के लिए हो रहा है. लेकिन सवाल उन किसानों का है, जिनकी फसल बर्बादी के कगार पर है.

डॉ शिशिर उपाध्याय

भोपाल। पहले अतिवृष्टि, बाढ़ का शिकार मध्यप्रदेश का किसान इन दिनों यूरिया के भारी संकट का सामना कर रहा है. यूरिया संकट के चलते राज्य में चौतरफा कोहराम और अराजकता के हालात बन गए हैं. यूरिया पाने के लिए सहकारी समितियों की चोखट पर लंबी-लंबी कतारों में किसान थक-हार कर अपना धैर्य खो रहे हैं. नतीजतन जगह-जगह से यूरिया से भरे ट्रक लुटे जाने, धरना, प्रदर्शन,



चक्काजाम, पथराव, सरकारी वाहन जला देने, कतारों में लगे किसानों

केन्द्र-राज्य में टकराव की नौबत यूरिया संकट के चलते प्रदेश में सियासत खासी गरमाई हुई है. पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भाजपा यूरिया संकट को लेकर हल्ला बोलते हुए प्रदेश भर में धरना-प्रदर्शन कर संकट के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है. सड़कों पर कमलनाथ सरकार मुर्दाबाद, सचिन यादव मुर्दाबाद, कांग्रेस मुर्दाबाद, किसानों को ठगने वाली सरकार नहीं चलेगी जैसे नारे गूँज रहे हैं. वहीं जरा कृषि मंत्री मंत्री सचिन यादव के ताजा बयान पर गौर करें, वो कहते हैं जबसे राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी है, तभी से केंद्र सरकार मप्र सरकार और किसानों से भेदभाव कर रही है.

को संभालने पुलिस द्वारा लाठी लहराने, बरसाने की खबरें तेजी से

बढ़ी है और सामने आ रही है. स्थिति ये है कि थानों से यूरिया वितरित किया जा रहा है. तमाम दावों के बावजूद हालात राज्य सरकार के काबू से बाहर होते दिख रहे हैं. किसानों के लिए यूरिया पाना इन दिनों किला फतह करने जैसा हो गया. इस मुद्दे को लेकर सियासत काफी गरमा गई है. सत्तापक्ष यूरिया की कमी का ठीकरा केन्द्र सरकार पर फोड़ रहा है, वहीं प्रमुख विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी का आरोप है, शेष पृष्ठ 7 पर

उम्मीदवार और बहुजन समाज पार्टी ने 40 ऐसे उम्मीदवार उतारे। एडीआर और नेशनल इलेक्शन वाच ने कहा कि उम्मीदवार वर्तमान 759 संसदों और 4063 विधायकों के 4,896 चुनावी हलफनामों में से 4822 का विश्लेषण किया। रिपोर्ट कहती है कि इस अवधि के दौरान महिलाओं के विरुद्ध अपराध के मामले बढ़े। लोकसभा चुनाव उम्मीदवारों की संख्या 38 से बढ़कर 126 हो गयी यानी ऐसे उम्मीदवार 231 फीसद बढ़ गये।

नागरिकता संशोधन विधेयक के बारे में पूर्वोत्तर के लोगों ने दिल्ली में भी प्रदर्शन किया। सड़क पर पोस्टरों के साथ उतरे लोगों ने बिल को वापस लेने की मांग की। इन लोगों ने स्ट्रिक को लंबे समय के

भारत की हथियार बनाने वाली कंपनियों ने ज्यादातर घरेलू मांगों को पूरा किया है। रिपोर्ट से साफ जाहिर होता है कि भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक (सऊदी अरब के बाद) होने के बावजूद डिफेंस इंडस्ट्रियल तैयार करने में अब तक विफल रहा है। ऐसे में अगर वैश्विक मतभेद की स्थिति में हथियारों की सप्लाई बंद हो जाती है तो भारत के लिए स्थिति चुनौतीपूर्ण हो जाएगी।

15 वर्ष में किसने संरक्षण दिया, कौन मौन रहा, यह सब जानते है : नरेंद्र सलूजा

किसी दबाव में आने वाली नहीं है, प्रदेश से माफिया राज हर हाल में खत्म होगा

माफिया राज खत्म करने की मुहिम का स्वागत करने की बजाय, माफियाओं के पैरोकार बन रहे हैं भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय

नवप्रदेश संवाददाता

भोपाल। मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा ने बताया कि प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने वर्षों से अवैध कार्यों को निरंतर अंजाम दे रहे माफियाओं के खिलाफ एक बड़ी मुहिम प्रदेश में प्रारंभ की है, जिसकी शुरुआत इंदौर से हो चुकी है। ऐसे माफियाओं के अवैध साम्राज्य को नेस्तनाबूद करने का व जनता को राहत देने



का कार्य निरंतर जारी है। इस मुहिम का प्रदेश भर में स्वागत हो रहा है, इंदौर की जनता भी बड़-चड़कर इस मुहिम का समर्थन कर रही है।इस समय माफियाओं के खिलाफ इस कार्यवाही का स्वागत करने की बजाय व जनता के साथ खड़े होने की बजाय भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव

माफियाओं की पैरोकारी कर, उनके समर्थन में खड़े हो रहे है, इस मुहिम पर सवाल उठा रहे है, जो कि बेहद शर्मनाक है। इस कार्यवाही में जिस प्रकार से अवैध खंस बार संचालित होने का मामला सामने आया है, 67 लड़कियाँ बरामद हुई है, जिसमें से कई लड़कियाँ बंगलादेश की होकर व कई

नाबालिग हो सकती है, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। सरकारी जमीन पर कब्जे से लेकर, कई अवैध निर्माण, प्रताड़ित व ब्लैकमेलिंग के मामले प्रतिदिन सामने आ रहे है।जनता बड़-चड़कर ऐसे माफियाओ के खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज करवाने प्रतिदिन सामने आ रही है।सरकार की कार्यवाही का सभी स्वागत व समर्थन कर रहे है, ऐसे समय इन माफियाओ के खिलाफ कार्यवाही का स्वागत करने के बजाय, उस पर सवाल उठाकर कैलाश विजयवर्गीय ने अपनी वास्तविकता बया कर दी है कि वो जनता के साथ ना होकर माफियाओ के साथ है। यह सही है पिछले 15 वर्ष की भाजपा सरकार में कैलाश विजयवर्गीय के साथ हेडिंग-पोस्टर में कई माफिया खुलेआम नजर आते थे, कई तरह के माफियाओ को उनका खुला संरक्षण रहता था, वे खुब पोषित होते थे।यह सभी भली-

भाँति जानते है।इसलिये माफियाओ के खिलाफ कार्यवाही पर उनका पेट दुखना स्वाभाविक है। लेकिन यह शिवराज जी की नहीं, कमलनाथ जी की सरकार है, वह किसी दबाव-प्रभाव में आने वाली बिलकुल नहीं है।ऐसे माफियाओं को जड़ से नेस्तनाबूद करेगी, उसको लेकर सरकार दृढ़ संकल्पित है। ऐसे माफियाओं पर सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी उन्हें कतई बख्शेगी नहीं। सलूजा ने कहा कि विजयवर्गीय बताये कि पिछले 15 वर्ष से प्रदेश में उनकी सरकार रही है, वे खुद इस दौरान कई जिम्मेदार पदों पर रहे है। क्या उन्होंने व उनकी सरकार ने ऐसे माफियाओं पर कार्रवाई का साहस कभी दिखाया या इनके खिलाफ कभी मुखरता दिखायी। जनता प्रताड़ित होती रही और ‘‘रोम जलता रहा और नीरो बंसी बजाता रहा की तर्ज पर वे और उनकी सरकार मौन रही।

कैग रिपोर्ट के बाद कमलनाथ सरकार ने तलब किया सिंचाई और नहरों के ठेकों का लेखा जोखा

सिंहस्थ और ई-टेंडर घोटालों के बाद सरकार सिंचाई और नहरों के ठेकों की जांच कराने जा रही है. सिंहस्थ और ई टेंडर के बाद भाजपा सरकार के समय की सिंचाई और नहरों के ठेकों में कैग की रिपोर्ट में आर्थिक गड़बड़ियां सामने आई हैं. बेस रेट से 10 फीसदी कम वाले ठेके जांच के दायरे में हैं.

नवप्रदेश संवाददाता

भोपाल। कांग्रेस सरकार एक-एक कर भाजपा सरकार में हुई गड़बड़ियों की जांच करा रही है. सिंहस्थ और ई-टेंडर के बाद कांग्रेस सरकार अब नहरों और सिंचाई के ठेकों की जांच करा रही है, खासतौर पर उन ठेकों



की जो बेस रेट से 10 फीसदी कम पर दिए गए, मैदानी निरीक्षण करके काम और भुगतान की स्थिति की जांच का आकलन किया जा रहा है. 10 करोड़ रूपयों तक के ठेकों की जांच कराई जा रही है. हर निर्माण कार्य में बेस रेट रखा जाता है. इससे कम प्राइज रेट देने वाले ठेकेदारों को टेंडर दिया गया है. इन सभी ठेकों के काम और भुगतान के ब्यौरा

फाइलों में नहीं मिला है. आर्थिक गड़बड़ियों को लेकर जल संसाधन विभाग ने अब सभी जिलों से रिपोर्ट तलब की है. सारे ठेकों की जांच शुरू हो गई है.

दोषियों पर होगी कड़ी कार्रवाई

जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा का कहना है कि नहरों और सिंचाई के ठेकों में भारी अनियमितताएं सामने

आई हैं. कैग की रिपोर्ट में सारी अनियमितताएं उजागर हुई हैं. ठेकों में हुई आर्थिक गड़बड़ियों की जांच कराई जाएगी. बरगी, पेंच, राजघाट सहित जितनी भी परियोजनाएं हैं, उनकी जांच रिपोर्ट मंगाई जा रही है, इनमें ग्वालियर, चंबल, मालवा, निमाड़ की सारी परियोजनाएं भी शामिल हैं. उन्होंने कहा कि जो भी दोषी हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

कब तक जांच का रोना रोएंगे

नहरों और सिंचाई के ठेकों की जांच को लेकर भाजपा सरकार के पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता का कहना है कि कब तक योजनाओं की जांच की बात करेंगे. अब तो एक साल हो गया है. कब तक जांच के नाम पर कार्रवाई का रोना रोएंगे.

राज्य सेवा परीक्षा में आवेदकों को उम्र में मिली एक साल की छूट

सीएम के दखल के बाद एमपीपीएससी ने जारी किया नोटिफिकेशन

पहले अधिकतम उम्र 40 वर्ष थी, अब 41 हुई ताकि नए आवेदकों को नुकसान न हो

भोपाल । मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग (एमपीपीएससी) की राज्य सेवा परीक्षा-2019 के लिए उम्मीदवारों को अधिकतम आयुसीमा में एक वर्ष की छूट मिलेगी। मुख्यमंत्री कमलनाथ के निर्देश के बाद पीएससी ने सोमवार देर शाम इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इसके मुताबिक राज्य सेवा परीक्षा के साथ ही राज्य वन सेवा परीक्षा में भी आवेदकों के लिए न्यूनतम उम्र 21 वर्ष और अधिकतम 41 वर्ष रहेगी। पहले अधिकतम आयुसीमा 40 वर्ष थी। हालांकि उम्मीदवारों की आयु की

गणना के लिए कट ऑफ डेट 1 जनवरी 2020 रहेगी, ताकि ओवरएज हो रहे उम्मीदवारों के साथ नए उम्मीदवारों को नुकसान न हो। तैयार, पीएससी के चेयरमैन डॉ. भास्कर चौबे ने बताया कि आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 9 दिसंबर से बढ़ाकर 12 दिसंबर की जा रही है। उल्लेखनीय है कि 2019 के नोटिफिकेशन में हुई देरी के कारण ओवरएज हुए उम्मीदवारों द्वारा आयु की गणना 1 जनवरी 2019 से करने की मांग की जा रही थी। ऐसे में जो उम्मीदवार 1 जनवरी 2020 के हिसाब से परीक्षा में शामिल होने के लिए योग्य हुए हैं, उन्हें बाहर होना प?ता। इसे देखते हुए पहले सामान्य प्रशासन विभाग के मंत्री डॉ. गोविंद सिंह के साथ मुख्यमंत्री कमलनाथ ने चर्चा की। बाद में विभाग की सचिव सोनाली पोक्षे वायंगणकर ने पीएससी की सचिव को पत्र लिखकर उम्र सीमा 41 करने का निर्देश दिया।

लोकार्पण



भोपाल (नवप्रदेश) । जनसम्पर्क मंत्री पी.सी. शर्मा ने अंजली काम्प्लेक्स में संप टैंक एवं पम्प हाउस का लोकार्पण किया ।

धरना प्रदर्शन

धरने पर बैठे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री कमलनाथ को सौंपा ज्ञापन

बच्ची को न्याय दिलाने को शिवराज ने दिया धरना, कांग्रेस ने कसा तंज

12 साल की बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या किए जाने के आरोपियों को सजा दिलाने के लिए धरने पर बैठे शिवराज

दुष्कर्म जैसे संवेदनशील विषय पर भी राजनीतिक नौटंकी कर रहे हैं शिवराज सिंह चौहान : कांग्रेस नेता शोभा ओझा

नवप्रदेश संवाददाता

भोपाल। आठ माह पूर्व 12 साल की एक बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या किए जाने के आरोपियों पर जल्द कार्रवाई किए जाने की मांग



को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सोमवार को धरने पर बैठ गए और उन्होंने मुख्यमंत्री कमलनाथ को ज्ञापन सौंपा। दूसरी ओर कांग्रेस ने चौहान के धरने को

राजनीतिक नौटंकी करार दिया है। राजधानी के मनुआभान टेकरी में आठ माह पूर्व 12 वर्षीय बालिका की दुष्कर्म के बाद पत्थरों से कुचलकर हत्या कर दी गई थी। इस

हत्याकांड के आरोपियों पर अबतक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसी को लेकर सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री चौहान बालिका की मां के साथ मासूम को न्याय दिलाने के लिए रोशनपुरा क्षेत्र में धरने पर बैठे। हैवानों की दरिंदगी का शिकार हुई बालिका की मां ने पुलिस पर गंभीरता से कार्रवाई न किए जाने का आरोप लगाया, और कहा कि उसकी बेटी के साथ दिन के उजाले में दुष्कर्म हुआ और उसकी हत्या कर दी गई। आरोपियों को आठ माह गुजर जाने के बाद भी सजा नहीं मिली है। पूर्व मुख्यमंत्री चौहान ने कहा, एक मां आठ माह से बेटी को

न्याय दिलाने के लिए भटक रही है। सवाल उठता है कि आखिर कहां जाए यह मां, ऐसा करूर काम करने वाले नर पिशाच हैं। वारदात को हुए आठ माह हो चुके हैं, मगर अब तक डीएनए रिपोर्ट नहीं आई है। आखिर कब तक इस बहन को न्याय मिलेगा। हमें अब एक ही बात करनी है कि बेटी के दोषियों को फांसी के फंदे पर लटक दिया जाए। धरने के बाद चौहान ने बालिका के परिवारवालों और बीजेपी नेताओं के साथ मुख्यमंत्री कमलनाथ से मुलाकात की और उन्हें एक ज्ञापन सौंपा। दूसरी ओर, पूर्व मुख्यमंत्री चौहान के धरने पर बैठने को लेकर

कांग्रेस ने तंज कसा है। प्रदेश कांग्रेस कमिटी की मीडिया विभाग की अध्यक्ष शोभा ओझा ने कहा, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दुष्कर्म जैसे संवेदनशील विषय पर भी राजनीतिक नौटंकी कर रहे हैं। यदि शिवराज सिंह ऐसे मुद्दों पर तनिक भी संवेदनशील होते तो उनके मुख्यमंत्रित्व काल में 47,000 से अधिक महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाएं नहीं हुई होतीं, बच्चियों और महिलाओं के साथ घटित होने वाले अपराधों में, प्रथम लगातार देश में नंबर वन न बना रहता।

कुत्तों के आतंक से लोगों को बचाने की कवायद में जुटा नगर निगम,

नवप्रदेश संवाददाता

भोपाल। बीते कई महीनों से भोपाल के अधिकांश इलाकों में कुत्तों का आतंक देखने को मिल रहा है. इन आवारा कुत्तों ने ना सिर्फ लोगों और बच्चों को काटा है बल्कि शहर में कई मासूमों की जान भी ले ली है. जबकि राजधानी में आवारा कुत्तों के आतंक से परेशान लोगों ने हर जगह आवेदन देकर शिकायत दर्ज कराई, लेकिन समाधान के लिए सबने हाथ खड़े कर दिए. यकीनन मामले की हजारों शिकायत भोपाल नगर निगम से लेकर मानव अधिकार आयोग तक पहुंची हैं. हालांकि कुत्तों के आतंक से लोगों को बचाने की कवायद अब नगर निगम अपने स्तर से करने में जुट गया है. नगर निगम का तर्क ये था कि भूखे रहने के कारण कुत्ते हमलावर होते हैं और अब इस समस्या से निपटने के लिए स्ट्रीट डॉग्स के लिए फीडिंग सेंटर बनाने जा रहा है. सेंटर में स्ट्रीट डॉग के खाने-पीने के इंताजम किए जाएंगे. संभागायुक्त कल्पना श्रीवास्तव ने बैठक कर ये फैसला लिया कि इन सेंटर्स को बनाकर पशु प्रेमियों के हवाले कर दिया जाएगा. उन्होंने नगर निगम को ये निर्देश भी दिए हैं कि शहर में संचालित प्लाउ के नौचे सकोरों में पानी भरकर रखने की व्यवस्था की जाए. वैसे इस वकत नगर निगम सेंटर्स के लिए जगह का चयन करने में जुटा हुआ है.



जनता की इजाजत से बनेंगे फीडिंग सेंटर

बरहवाल, जहां ये फीडिंग सेंटर बनेंगे वहां के लोगों को परेशानी ना हो इस बात का भी खास ख्याल रखा जा रहा है. निगम का आदेश है कि स्ट्रीट डॉग के लिए जो फीडिंग सेंटर बनाए जाएंगे, उसके लिए कॉलोनियों की एनओसी लेना जरूरी है.

न्यूज गैलरी

नगर निगम की गाड़ियों पर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं



रेश ड्राइविंग करते नगर निगम के ड्राइवर, दुर्घटना हुई तो बिना नम्बर जिम्मेदारी कैसे करेंगे तय

भोपाल एक सरकारी विभाग दूसरे विभाग के नियमों की परवाह नहीं करते । ऐसी मनमानी का एक और नदूना नगर निगम के कचरा कलेक्शन वाहन हैं । इन वाहनों को काम के लिए सड़क पर तो उतार दिया गया है, लेकिन अभी तक रजिस्ट्रेशन नम्बर डिस्प्ले नहीं किए गए हैं । इन वाहनों के ड्राइवर रेश ड्राइविंग करते देखे गए हैं । किसी को टक्कर मार दी तो किसे पकड़ा जाएगा ? उल्लेखनीय है कि स्वच्छता सर्वेक्षण में अच्छी रैंकिंग पाने के लिए भोपाल नगर निगम काफी प्रयास कर रहा है । आधिकारिक सुत्रों की मानें तो कचरा कलेक्शन के लिए नगर निगम ने कुछ समय पूर्व करीब तीन दर्जन गाडियां खरीदी हैं । इन गाडियों पर आगे-पीछे या साइड में कहीं भी रजिस्ट्रेशन नम्बर नहीं लिखा गया है, जबकि ये वाहन कई दिनों से शहर में कचरा कलेक्शन कार्य में लगाए जा चुके हैं ।

जिम्मेदार विभागों को भी नहीं देते दिखाई

लोगों ने शहर के भीड़ वाले इलाकों, बाजारों, चौराहों/तिराहों पर रेश ड्राइविंग देखी है । यदि कोई इन वाहनों से कोई दुर्घटना हो जाती है तो दोषी को कैसे पकड़ा जाएगा ? इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा ? इन वाहनों को काम के लिए सड़क पर तो उतार दिया गया है, लेकिन अभी तक रजिस्ट्रेशन नम्बर डिस्प्ले नहीं किए गए हैं । इन वाहनों के ड्राइवर रेश ड्राइविंग करते देखे गए हैं । किसी को टक्कर मार दी तो किसे पकड़ा जाएगा ?

बड़ी कार्रवाई / 50 साल पुराना पत्रकार भवन 12 घंटे में जमींदोज

हाईकोर्ट से लीज रिन्युअल की रिक््यू पिटीशन खारिज होने के बाद रविवार रात शासन ने लिया फैसला

कार्रवाई में शामिल अमले से कहा गया- बड़ा सफाई अभियान चलाना है...सुबह पांच बजे एक्शन शुरू

भोपाल । मालवीय नगर स्थित पत्रकार भवन को 12 घंटे चली कार्रवाई के बाद जमींदोज कर दिया गया । पांच पोकलेन, पांच जेसीबी, दस डम्पर की मदद से यह कार्रवाई हुई । विवाद की आशंका को देखते हुए मौके पर 150 से ज्यादा पुलिस बल तैनात किया गया । हाईकोर्ट द्वारा भवन की लीज रिन्युअल की रिक््यू पिटीशन खारिज किए जाने के बाद भवन जमींदोज किया गया । शहर एसडीएम जमील खान ने भवन को सील कर दिया था । रविवार दोपहर में जनसंपर्क विभाग के अफसरों ने कलैक्टर तरुण पिथोड़े की जर्जर भवन को गिराने के निर्देश दिए थे । रविवार देर रात जिला प्रशासन, नगर निगम और पुलिस के अफसरों की बैठक में तय हुआ कि तड़के भवन को जमींदोज करने की कार्रवाई की जाएगी । लेकिन नीचे के अमले को यह जानकारी दी गई कि एक बड़ा स्वच्छता अभियान चलाना है । सोमवार तड़के 4 बजे एडीएम सतीश कुमार एस ने कंट्रोल रूम में अफसरों की बैठक ली । सुबह 5 बजे से भवन गिराने की कार्रवाई शुरू की गई, जो शाम 5 बजे तक जारी रही । दोपहर 2 बजे तक भवन का अधिकांश हिस्सा धराशायी किया जा चुका था । इसके बाद एक कमरे में रखे सामान को पंचनामा बना कर जनसंपर्क विभाग पहुंचाया गया और शेष हिस्से को भी ढहा दिया गया ।

आगे क्या.. मीडिया सेंटर बनेगा

पत्रकार भवन की जमीन पर राज्य सरकार मीडिया सेंटर बनाएगी । इसमें ऑडिटोरियम, बैंकट हॉल काफ़ेस रूम के साथ आर्ट गैलरी भी होगी । जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने बताया कि देश- विदेश के मीडिया सेंटरों का अध्ययन करने के बाद इसकी डिजाइन तैयार कराई गई है । इसमें पत्रकारों के लिए गेस्ट रूम भी होगा । पत्रकार भवन में सामाजिक कार्यक्रम भी आयोजित हो सकेंगे । जिम क्लब और रेस्तरां भी होगा । पत्रकार भवन को धराशायी करने के बाद इसका सीएंडडी वेस्ट फिलहाल यहीं पड़ा रहेगा । इस स्थान को टेम्परेरी सीएंडडी वेस्ट कलेक्शन सेंटर बनाया जा रहा है । यहां मालवीय नगर, टीटी नगर और वार इमली क्षेत्र के सीएंडडी वेस्ट को उधप किया जाएगा । अमले कुछ महीनों में आदमपुर छावनी में सी एंड डी वेस्ट का प्लांट लगने पर इस वेस्ट को वहां पहुंचा दिया जाएगा । सोमवार सुबह छह बजे नगर निगम कमिश्नर बी विजय दत्ता मौके पर पहुंचे । उन्होंने अफसरों को कहा कि दोपहर दो बजे तक भवन गिराना है । मशीनों की संख्या बढ़ाई । यहां दो पोकलेन काम कर रही थीं ।

संपादकीय

नागरिकता संशोधन विधेयक स्वागतये

लोकसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक बहुमत से पारित हो गया। अब इसे राज्यसभा में पेश किया जाएगा। उम्मीद है कि वहां भी यह विधेयक पारित हो जाएगा। लोकसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक पर हुई इस चर्चा के दौरान कांग्रेस सहित अनेक विपक्षी दलों ने इस विधेयक का जमकर विरोध किया। उनका कहना है कि नागरिकता संशोधन विधेयक असंवैधानिक है। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि इस बिल के जरिए सरकार अल्पसंख्यकों को निशाना बना रही है। इसके जवाब में गृहमंत्री अमित शाह ने स्पष्ट किया कि नागरिकता संशोधन बिल राष्ट्र हित में है और इसमें अल्पसंख्यकों के प्रति किसी भी तरह का कोई अन्याय करने का सरकार का कोई इशदा नहीं है। उन्होंने कांग्रेस को आड़े लेंते हुए जवाबी हमला किया कि कांग्रेस ने धर्म के आधार पर देश का बंटवारा किया था। कांग्रेस ने अगर धर्म के आधार पर देश का विभाजन नहीं किया होता तो आज उन्हें नागरिकता संशोधन विधेयक लाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बहरहाल लोकसभा में यह बिल विपक्ष के भारी विरोध के बीच पारित हो गया है। लोकसभा में इस बिल के पारित होने के बाद पड़ोसी राज्यों से भारत में आए लाखों हिन्दू और सिख खुश हैं। हिन्हें अब आसानी से भारतीय नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। निश्चित रूप से नागरिकता संशोधन विधेयक राष्ट्रहित में है और इसका पूरे देश को एक स्वर में स्वागत करना चाहिए। पूर्वोत्तर राज्यों में इस विधेयक को लेकर विरोध के स्वर सुनाई पड़ रहे हैं। उन्हें भी विवास में लेने की आवश्यकता है। उन्हें यह भरोसा दिलाना होगा कि इस विधेयक से उनके हितों पर कोई कुटाराघात नहीं होगा। ऐसा लगता है कि विपक्ष सिर्फ विरोध के नाम पर ही इस विधेयक का विरोध कर रहा है। जबकि यह इस देश की विडम्बना है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे पड़ोसी राज्यों से लाखों की संख्या में भारत आए हिन्दुस्तानी आज अपने ही घर में बेगाने होकर रह गए हैं। ऐसे हिन्दुओं को यदि भारत नागरिकता नहीं देता तो दुनिया का और कौन सा ऐसा देश है जहां इन्हें नागरिकता मिल जाएगी। बेहतर होगा कि विपक्ष नागरिकता संशोधन विधेयक का विरोध छोड़ इस विधेयक के मार्ग में अनावश्यक बाधा खड़ी न करें। इस विधेयक के जरिए देश को धार्मिक आधार पर बांट नया जा रहा है बल्कि उन लाखों हिन्दुओं, सिखों और बौद्धों को न्याय दिया जा रहा है। जो पिछले सात दशकों से अपने अधिकार से वंचित रहे हैं।

विचार

रेप-मर्डर और यौन हिंसा

हैदराबाद रेप-मर्डर के चारों आरोपियों के पुलिस मुठभेड़ में मारे जाने के बाद देशवासियों के एक बड़े हिस्से ने राहत की सांस लेनी शुरू ही की थी कि उज़ाव रेप पीड़िता की मौत ने दोबारा सबको मायूसी की चपेट में ले लिया। घटनाओं का यह क्रम बताता है कि हम नृशंस घटनाओं से उद्ध्वलित तो होते हैं लेकिन समाज और सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए कुछ ठोस नहीं कर पाते। 2012 में दिल्ली की सड़कों पर निर्भया के साथ हुई हैवानियत ने देश में एक जागृति पैदा की। फिर पिछले साल ऐसी दूसरी लहर समीटू मूवमेंट के रूप में उभरी जब कार्यस्थलों पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न मुद्दा बना। करीब पांच साल के अंतर पर आई इन हलचलों का समाज के मन-मस्तिष्क पर कुछ न कुछ प्रभाव जरूर पड़ा होगा, लेकिन निश्चित रूप से यह इतना कारगर नहीं था कि ऐसी घटनाओं में थोड़ी भी कमी महसूस हो सके। यौन हिंसा के मामलों को लेकर हमारे प्रशासनिक तंत्र की प्रतिक्रिया कमोबेश पहले जैसी ही रही। कुछ मामले ऐसे भी दिखे, जिनमें स्थानीय जनमत बलात्कारियों के पक्ष में जाता दिखा। कनुआ से लेकर उज़ाव और शाहजहांपुर तक ऐसे कई मामले हैं जहां ताकतवर आरोपी के सामने प्रशासनिक तंत्र पस्त नजर आया। कभी लड़की के चाल चरित्र को तो कभी उसके व्यवहार को दोष देने वाले बयान भी कम नहीं हुए। ऐसे में यह सवाल वाजिब है कि क्या हम और हमारी सरकार इन घटनाओं को महज एक तात्कालिक सनसनी के ही रूप में लेते रहने को अभिशप्त हैं? जब कोई बड़ी घटना हो जाए तो उसके आरोपियों को फंसी देने की मांग करना और फिर सरकार की तरफसे कोई सुरां छोड़ दिए जाने पर खुशी से उछल जाना! इस हकीकत की तरफ हमारा ध्यान कम ही जाता है कि बलात्कार के मामलों में दोष साबित होने और सजा पड़ने का अनुपात जहां का तहां अटका पड़ा है।

टेक ज्ञान

जीमेल में आया नया फीचर

नई दिल्ली। गूगल की ईमेल सर्विस Gmail में एक नया फीचर जुड़ा है। इस फीचर का नाम ‘attach an email to an email’ है। अब यूजर्स को ईमेल फॉरवर्ड करने के लिए पहले उसे डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गूगल अब जीमेल में ईमैल्स को अटैचमेंट के तौर पर फॉरवर्ड करने की सुविधा दे रहा है। अगर अभी की बात करें तो यूजर्स को अटैचमेंट वाले ईमैल्स को फॉरवर्ड करने के लिए पहले उसे डाउनलोड करना पड़ता है और फिर उन अटैचमेंट्स को एक-एक करके ऐड करना होता है। नए फीचर में अगर आप कोई ई-मेल किसी को फॉरवर्ड करना चाहेंगे तो आपको इसे अटैचमेंट डाउनलोड नहीं करना होगा, बल्कि आप इसे भेजे जाने वाले ई-मेल में सीधे ड्रेग करके भेज पाएंगे। गूगल ने अब अटैचमेंट वाले ईमैल्स को फॉरवर्ड करना आसान कर दिया है। अब ईमेल डाउनलोड या अपलोड करने की प्रक्रिया को ऑटोमैटिक कर दिया गया है। इसके लिए गूगल ने जीमेल में एक खास बिल्ड इन यूजर इंटरफेस दिया है जो एक साथ कई ईमेल को फॉरवर्ड करने की सुविधा देता है।

पाठकों की बात

बलात्कार के केस

में, अब ना होगी डेर

बलात्कार के केस में, अब ना होगी डेर। केवल गोली मारकर ,करना होगा डेर। न्याय मिले यदि डेर से, वो होगा अन्याय। भय बिनु होय न प्रीत का, शुरु हुआ अध्याय। रावण चारो चित्त है, हुआ कलेजा शान्त। दिल्ली से गुजरात तक, खुश है सारे प्रान्त।
बलराम निगम

भारत की व्यवस्था हो गई

है बहुत निराशाजनक

भारत की व्यवस्था हो गई है ब ह ु त निराशाजनक , सारी शक्ति ऊपर बैठे चंद हाथों मे रह गई है सिम्ट कर, नीचे बैठे लोग होते रहते हैं शिकार ज्यादाती का अक्सर और कुछ नहीं कर पाकर रह जाते हैं मन मसोस कर। होगा ऐसा कब तक आखिर ?
अर्पित अनाम

पत्र, प्रतिक्रियाएं, सोशल मीडिया

ख़ास प़ाती

कब तक चिखूंगी, कब तक चिल्लाऊंगी

कब तक चिखूंगी, कब तक चिल्लाऊंगी आखिर कब तक अपनी अस्मिता की लाज बचाने की खातिर दूसरों के सामने गिड़गिड़ाउंगी। कभी नोची गई, कभी बीच सड़क पर अंग भंग करके फेंकी गई, कल भी जलाई गई थी मैं प्रथा के नाम पर, और आज मैं हैवानियत के नाम पर आखिर कब तक आहुति दी जाऊंगी। मुझे खुद से प्रयास करना होगा, अब मोमबती नही हाथ में मशाल लेकर चलना होगा, बहुत बन चूँकि मेनका, उर्वशी, अब चंडी बनकर इन हैवानो का रक्त पीना होगा।
पूजा बहार

बंधन को निभा लूँ यही बहुत है

बंधन को निभा लूँ यही बहुत है ये दर्द ही सही ए मेरे हमदर्द दिल की बातें तो दिल ही जाने है जुनून तेरा निभा लूँ यहीं बहुत है।
बेनू सतीश कौंत

कुछ लोग कहते है कि बेटियों को

कुछ लोग कहते है कि बेटियों को हथियार दो जिस से वो अपनी सुरक्षा कर सके? आप बेटों को संस्कार क्यों नहीं देते,जिस से वो ये दुक्मर्न ना कर सके ? उन नीचों के लिए हम अपनी बहन बेटियों को हिंसक बना दे?? क्या इतना आसान है एक महिला या लड़की के लिए किसी की जान लेना,जिनका दिल इतना नरम होता है कि एक चींटी भी नहीं मार सकती। क्यों लड़किया किसी लड़के का बलात्कार कर उसे जिंदा नही जलाती?? खोत पुरुष वर्ग में है तो उपचार उन की मानसिकता का हो।

संध्या चतुर्वेदी

उपेन्द्र प्रसाद

मामला एक बार फिर सुप्रीम

कोर्ट के पाले में है। उसे यह निर्णय करना है कि वह

2018 के आदेश की समीक्षा

करे या सरकार को साफ़साफ़

शब्दों में यह आदेश दे कि

ओबीसी की तरह ही एससी

और एसटी के त्रीनी लेयर में

आने वाले लोगों को आरक्षण

से वंचित कर दिया जाय।

इन्दिरा साहनी केस का

फैसला 1992 में आया था।

तब से अबतक 27 साल बीत

चुके हैं और इस बीच एससी

और एसटी आबादी को फाइल

नी बदल चुका है। इसे देखते

हुए सुप्रीम कोर्ट कह सकता है

कि 2018 का आदेश 1992 के

आदेश का उल्लंघन नहीं,

वर्षोंकि 27 सालों में स्थितियां

बदल चुकी हैं। सबसे बड़ी बात

यह है कि इससे एससी और

एसटी आरक्षण पर किसी

तरह का असर नहीं पड़ता।



डॉ. शिशिर उपाध्याय

आग लगने की अब

तक जो भी बड़ी घटनाएं

हुई हैं, चाहे वह अवैध

रुस्त से चलाए जा रहे

कारखानों में हो या फिर

किसी होटल, बाजार

आदि में, सबमें यही

देखा गया है कि वहां

सुरक्षा संबंधी नियमों की

अनदेखी की गई थी।

दिल्ली की अनाजमंडी में

लगी आग से दम घुटने

और झुलस कर

तिरलीस लोगों की मौत

ने एक बार फिर

प्रशासन की लापरवाही

और असवेदनशीलता को

रेखांकित किया है।

अभिव्यक्ति

एससी, एसटी और क्रिमी लेयर

सरकार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश से एतराज क्यों?

पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में केन्द्र और राज्य सरकारों से कहा कि वह अनुसूचित जातियों और जनजातियों को दिए जा रहे आरक्षण में त्रीमी लेयर का प्रावधान खोले। सुप्रीम कोर्ट इन समुदायों के लिए आरक्षण में प्रमोशन के मामले की सुनवाई कर रही थी। सुनवाई प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्र की अध्यक्षता वाले एक बेंच में हो रही थी। आरक्षण में प्रमोशन को सही मानते हुए कोर्ट ने कुछ शर्तें रख दीं और उसके साथ ही सभी प्रकार के एससी-एसटी के आरक्षण में इन वर्गों के त्रीमी लेयर को बाहर रखने को कहा। लेकिन केन्द्र और राज्य सरकारें सुप्रीम कोर्ट को उस आदेश को मानने को तैयार नहीं हैं। इस बीच सरकारी सेवाओं में नियुक्तियों और शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए कई बार विज्ञापन आए, लेकिन एससी और एससी उम्मीदवारों के लिए त्रीमी लेयर नहीं लगाया गया। त्रीमी लेयर लगाना तो दूर अभी तक एसएसी और एसटी के लिए त्रीमी लेयर का क्राइटेरिया तक तय नहीं किया गया है।

वैसे त्रीमी लेयर ओबीसी के लिए पहले से ही लागू है और इसका क्राइटेरिया भी तैयार है। यदि इसी क्राइटेरिया को एससी और एसटी के लिए भी स्वीकार कर लिया जाता है, तो फिर वैसा करने के लिए अलग से कोई कमिटी बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन जब सरकार इसके लिए तैयार ही नहीं हो, तो फिर बात ही कुछ अलग हो जाती है। इस बीच एससी और एसटी समुदाय के ही कुछ लोग फिर अदालत का रुख कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि कोर्ट हस्तक्षेप कर सरकारों को उसके आदेश को मानने के लिए बाध्य करे। सरकार को इसके लिए नोटिस भी जारी किए गए हैं और अब सरकार कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट अपने उस आदेश की समीक्षा करे और वह समीक्षा 7 जजों के बेंच के द्वारा की जाय, क्योंकि जिस बेंच ने त्रीमी लेयर का आदेश दिया, वह 5 जजों की बेंच था।

आखिर सरकार कोर्ट के आदेश का पालन क्यों नहीं कर रही है? इन्दिरा साहनी केस के नाम से प्रचारित मंडल केस में जब सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी के लिए त्रीमी लेयर का प्रावधान किया था, तो उसने उसे झट से स्वीकार कर लिया था और प्रसाद कमिटी बनाकर त्रीमी लेयर के मानदंड भी तय कर दिए थे, लेकिन जब एससी और एसटी का मामला

आया तो सरकार इसके लिए तैयार नहीं। कहने की जरूरत नहीं कि इसका मुख्य कारण राजनैतिक ही है। सरकार नहीं चाहती कि इस तरह के फैसले से दलितों और आदिवासियों के शक्तिशाली दबाव समूहों को नाराज किया जाय। आदिवासियों को दबाव समूह बहुत मजबूत तो नहीं है,



लेकिन दलितों का दबाव समूह बहुत मजबूत है और सत्ता में इसका दखल भी है। त्रीमी लेयर के प्रावधान से इस दबाव समूह के लोग प्रभावित होंगे। समूह के अधिकांश लोगों के बच्चों को आरक्षण का लाभ मिलना समाप्त हो जाएगा। इस दबाव समूहों के लोगों का सत्ता पर काबिज लोगों के साथ जबर्दस्त गठबंधन है और यह इसी गठबंधन का असर है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने से इनकार कर रही है और उल्टे उसे इसकी समीक्षा करने के लिए कह रही है।

वैसे इसका एक तकनीकी पक्ष भी है। इन्दिरा साहनी के जिस केस में ओबीसी के लिए त्रीमी लेयर का प्रावधान किया गया था, उसी केस में यह भी कहा गया था कि एसएसी और एसटी में इसे लागू करने की जरूरत नहीं है। इसका कारण बताते हुए कहा गया था कि एससी और एसटी समाज का सबसे पिछड़ा हुआ समुदाय है। वह बेंच 9 जजों का था। जिस बेंच ने पिछले साल एससी और एसटी में त्रीमी लेयर लगाने को कहा, वह पांच सदस्यों का बेंच था। इसलिए तकनीकी मसला यह है कि पांच जजों का बेंच 9 जजों के बेंच के फैसले को कैसे पलट सकता है। इसी को आधार बनाकर केन्द्र सरकार सुप्रीम कोर्ट से अपने आदेश की समीक्षा करने को कह रही है। लेकिन वह चाहती है कि 7

दलों का समाधान से ज्यादा राजनीति पर ध्यान ?

उपहार सिनेमा कांड के बाद आग लगने की यह दूसरी सबसे बड़ी घटना है, जिसमें इतने लोगों की मौत हो गई। इसी साल करोलबाग के एक होटल में लगी आग से करीब चौदह लोगों की मौत हो गई थी। इसके अलावा ऐसे छिटपुट हादसे होते रहते हैं, जिनमें लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। अनाजमंडी की जिस इमारत में आग लगी, वहां अवैध रूप से कारखाना चल रहा था, जिसमें प्लास्टिक और कामाज से चीजें बनाई जा रही थीं। इसी के एक हिस्से में वहां काम करने वाले मजदूर रहते थे। रविवार की सुबह जब आग लगी, तो वे वहां सो रहे थे। सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद थीं, इसलिए ज्यादातर लोगों की दम घुटने से मौत हो गई। कुछ लोग बाहर नहीं निकल पाए और झुलस गए। इसमें कई गंभीर रूप से घायल हैं। आग लगने की वजह बिजली के तारों का गरम होकर जल उठना बताया जा रहा है। हालांकि बिजली के मोटर सही अवस्था में पाए गए हैं, इसलिए इसकी वजह कोई दूसरी भी हो सकती है। अभी इसकी छानबीन चल रही है।

अनाजमंडी के कारखाने में मारे गए लोग भी मालिकों और प्रशासन की इसी लापरवाही की भेंट चढ़ गए। दिल्ली में बड़ते प्रदूषण के मद्देनजर अदालतें अनेक मौकों पर फटकार लगा और समूत्र निर्देश दे चुकी हैं कि रिहाइशी इलाकों में चल रहे प्रदूषण फैलाने वाले कारखानों को हटया जाए। मगर फोरी सक्रियता के बाद हर बार लंबी शिथिलता पसर जाती है। फिर दिल्ली के बहुत सारे इलाके ऐसे हैं, जो अनधिकृत कॉलोनी के रूप में बसे थे और सरकार ने उन्हें अधिकृत घोषित कर दिया। इससे वहां बिजली, पानी, सड़क, सीवर की व्यवस्था तो हो गई, पर उनकी बसावट इस तरह सघन है कि वहां दमकल की गाड़ियों आदि के पहुंचने में भी कठिनाई आती है। वहां बड़े पैमाने पर ऐसे कारखाने चल रहे हैं, जिन्हें यह मान कर चलने दिया जाता है कि वे प्रदूषण नहीं

फैलाते। इसी तरह दिल्ली के गांवों में बड़े पैमाने पर ऐसी गतिविधियां चल रही हैं। दोनों सरकारों को ऐसे कारखानों को लेकर कोई व्यावहारिक नीति बनाने की जरूरत है, ताकि मौत की वजह बनने वाले हादसे दुहराए न जा सकें। हर हादसे के बाद तमाम गड़बड़ियां ठीक करने के संकल्प दोहराए जाते हैं।



दिल्ली अग्निकांड

जांच चलती है। कुछ दोषी पकड़े जाते हैं लेकिन फिर सब कुछ भुला दिया जाता है। आज भी दिल्ली के कई रिहायशी इलाकों में फैक्ट्रियां लगाई जा रही हैं और जरूरी सुरक्षा इंतजामों को ताक पर रखा जा रहा है। अनाज मंडी के मामले में हालात ऐसे ही थे। बताया जा रहा है कि इन कारखानों को खाली करने के लिए एक महीने पहले नोटिस भेजा गया था लेकिन नोटिस की अनदेखी की गई।आग लगने की अब तक जो भी बड़ी घटनाएं हुई हैं, चाहे वह अवैध रूप से चलाए जा रहे कारखानों में हो या फिर किसी होटल, बाजार आदि में, सबमें यही देखा गया है कि वहां सुरक्षा संबंधी नियमों की अनदेखी की गई थी। फिर सवाल है कि ऐसी जगहों पर

जजों का बेंच इसकी समीक्षा करे। पर सवाल उठता है कि यदि 7 जजों के उस बेंच ने समीक्षा करके त्रीमी लेयर को उचित उधराया तो फिर पुराना सवाल बना ही रहेगा कि 7 जजों का बेंच 9 जजों के बेंच के फैसले को कैसे पलट सकता है। इसकी तर्क तो यही कहता है कि केन्द्र सरकार को कहना चाहिए कि 11 जजों का बेंच बनाया जाय, जो 5 जजों और इन्दिरा साहनी केस वाले 9 जजों के आदेशों की समीक्षा करे।

मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के पाले में है। उसे यह निर्णय करना है कि वह 2018 के आदेश की समीक्षा करे या सरकार को साफ साफ शब्दों में यह आदेश दे कि ओबीसी की तरह ही एससी और एसटी के त्रीमी लेयर में आने वाले लोगों को आरक्षण से वंचित कर दिया जाय। इन्दिरा साहनी केस का फैसला 1992 में आया था। तब से अबतक 27 साल बीत चुके हैं और इस बीच एससी और एसटी आबादी को प्रोफाइल भी बदल चुका है। इसे देखते हुए सुप्रीम कोर्ट कह सकता है कि 2018 का आदेश 1992 के आदेश का उल्लंघन नहीं, क्योंकि 27 सालों में स्थितियां बदल चुकी हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इससे एससी और एसटी आरक्षण पर किसी तरह का असर नहीं पड़ता। समुदाय के रूप में उन्हें आरक्षण मिलता रहेगा। फर्क सिर्फ यह पड़ेगा कि उसमें जो संपन्न और समृद्ध होकर त्रीमी लेयर में आ गए हैं, उनकी जगह उन्हीं समुदायों के गरीब लोगों को उस आरक्षण के तहत नियुक्तियां और प्रवेश मिलेंगे। इसके कारण एससी और एसटी समुदायों में समृद्धि और संपन्नता का आधार और विस्तृत होगा और उनमें गरीबी और पिछड़ापना दूर करने में ज्यादा सफलता मिलेगी।

आरक्षण व्यवस्था ने दलितों और आदिवासियों के सशक्तिकरण में उल्लेखनीय भूमिका निभाई है, लेकिन इसके कारण उन समुदायों में जबर्दस्त विषमता पैदा कर दी है। जिस तर्क से दलितों और आदिवासियों को आरक्षण दिया गया था कि वे समाज के अगड़े तबकों से बराबरी की प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते, उसी तर्क से अब उनके बीच त्रीमी लेयर लगाया जाना चाहिए कि गरीब और पिछड़े दलित संपन्न दलितों के साथ बराबरी का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। (**संवाद**)

निगरानी रखने वाला तंत्र तब तक क्यों आंखें बंद किए रखता है, जब तक कि कोई बड़ा हादसा नहीं हो जाता। छिपी बात नहीं है कि इस तरह छोटे पैमाने पर चलाए जाने वाले कारखानों में अक्सर आग लगने, भूकंप आदि की स्थितियों में सुरक्षा मानकों के अनुरूप निकास, अग्निशमन यंत्र, बिजली के तारों आदि पर समुचित ध्यान नहीं दिया जाता। इस्की बड़ी वजह है कि संबंधित महकमे इन लापरवाहियों की अनदेखी करते हैं या फिर किसी सांटागांठ या प्रभाव के चलते उनके खिलाफ कड़ाई नहीं करते। विचित्र है कि ऐसे बहुत सारे कारखाने सघन बसे रिहाइशी इलाकों में चलते हैं, जहां एक इमारत की आग बहुत बड़े हादसे का सबब बन सकती है, पर वहां भी प्रशासन को लापरवाह ही देखा जाता है।फैक्ट्री चलाने वालों के पास ना तो फायर की एनओसी थी, ना ही उन्होंने यहां फायर सेफ्टी का कोई इंतजाम किया हुआ था। हद तो यह कि सात महीने पहले ही इस इमारत में आग लगी थी फिर भी कोई इंतजाम नहीं किया गया। नियमों के हिसाब से घरेलू इंडस्ट्री में ज्यादा से ज्यादा 9 लोगों को रखा जा सकता है और बिजली का लोड 11 किलोवॉट से ज्यादा नहीं हो सकता लेकिन यहां सैकड़ों कमचारी काम कर रहे थे। इमारत में वेंटिलेशन का भी पर्याप्त इंतजाम नहीं था। सचाई यह है कि राजधानी में ऐसी हजारों इमारतों में गुपचुप कारखाने चलाए जा रहे हैं, जहां मामूली चूक से बड़ा हादसा हो सकता है। भयानक घटनाओं के बाद प्रश्नचार्क का एक व्यवस्थित तंत्र सामने आता है, जो थोड़ा-बहुत हिल-डुलकर दोबारा अपनी जगह पर वापस लौट आता है। सवाल है कि लोगों की जान के साथ खिलवाड़ का यह सिलसिला कब तक चलता रहेगा। देश के अन्य महानगरों का हाल भी कोई बहुत अच्छा नहीं है। मुंबई में हाल ही में आग लगने की कई घटनाएं हुई हैं।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं)

लगु कथा

संवेदनशीलता

हैं सौंप दी। “आखिरकार लम्बी बीमारी के बाद पोप जॉन पॉल द्वितीय नहीं रहे।” पोप जॉन पॉल द्वितीय पर सभी स्क्रिप्ट लिखने और वीडियो एडिटिंग करवाने की जिम्मेदारी मुझे दी गई थी। दरअसल मैंने ही अपने बॉस को बताया था कि पोप की सेहत लगातार गिर रही है। ऐसा लगता है कि ये जल्दी भगवान को फिर हो सकते हैं। न्यूज चैनल के लिए ये एक बहुत बड़ी खबर होगी। ऊंचे तबके के लोगों की इस खबर पर पेनी नजर है। क्यों न पोप पर कुछ अच्छे पैकेज पहले से बनाकर रखे जाएँ। कभी इनकी मौत हो गई तो फिर हम दूसरे चैनलों के मुकाबले इसे अच्छे से कवर कर पाएंगे। बॉस को ये आइडिया पसन्द आया और उन्होंने ये जिम्मेदारी मुझे

आज का इतिहास

नई दिल्ली, । भारत और विश्व के इतिहास में 11 दिसंबर की प्रमुख घटनाएं इस प्रकार हैं- 1687 -ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में नगर निगम बनाया। 1845-प्रथम आंग्ल-फ्रिख युद्ध में शुरू। 1858 बकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और यदुनाथ बोस कलकत्ता विश्वविद्यालय से कला विषय के पहले स्नातक बने। 1911 मिश्र के उपन्यासकार नाबिक महन्त का जन्म। वह साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले अरबी लेखक थे। 1921-महाकवि भरतियार के नाम से विख्यात तमिल कवि सुब्रह्मण्य भारती का जन्म हुआ। उन्हें बकिम चंद्र की अमर रचना वन्देमातरम बहुत प्रिय थी और उन्होंने इसका उसी लय में तमिल में पद्यानुवाद किया था। 1922- हिंदी सिनेमा के हर्दिल अजीज अभिनेता एवं राज्यसभा के पूर्व सदस्य दिलीप कुमार का जन्म हुआ।



इस हेतु पॉवर कंपनी प्रबंधन वे प्रति आधार व्यक्त किया और कंपनी को सतत उंचाईयों की ओर ले जाने के लिए संकल्प दोहराया। इसी क्रम में महाप्रबंधक (मानव संसाधन), होल्डिंग कंपनी एच.के. पाण्डे और अति महाप्रबंधक जनसंपर्क विजय मिश्रा ने भी अपने विचारों की अभिव्यक्ति दी।

न्यूज गैलरी

जमशेद फिक्सिंग के दोषी, अनवर और एजाज ने भी कबूला

लंदन ए.। पाकिस्तान के पूर्व बल्लेबाज नासिर जमशेद को टी20 स्पोर्ट फिक्सिंग मामले में साथी क्रिकेटरों को रिश्तत देने की साजिश में शामिल होने का दोषी पाया गया। दो अन्य व्यक्तियों युसूफ अनवर और मोहम्मद एजाज ने पीएसएल खिलाड़ियों को रिश्तत की पेशकश की बात कबुल की है। तीनों की सजा फरवरी में तय की जाएगी। जांच के दौरान पुलिस ने पाया कि 2016 में बांग्लादेश प्रीमियर लीग में भी फिक्सिंग का प्रयास किया गया था जबकि पीएसएल 2017 में मैच फिक्स किए गए। दोनों मामलों में इस सलामी बल्लेबाज ने एक ओवर की पहली दो गेंदों पर रन नहीं बनाए, जिसके बदले में उसे पैसे दिये गए। जमशेद ने पीएसएल में नौ फरवरी को इस्लामाबाद युनाइटेड और पेशावर जल्मी के बीच दुबई में खेले गए मैच में खिलाड़ियों को फिक्सिंग के लिए उकसाया था।

प्रतिबंध: वाडा के खिलाफ अदालत जाएंगे: पुतिन
पेरिस ए.। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी (वाडा) की तरफसे रूस पर लगाये प्रतिबंध को लेकर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि वाडा का निर्णय ओलंपिक चार्टर का उल्लंघन है और रूस के पास इसके खिलाफ अदालत जाने के सभी कारण मौजूद हैं। वाडा ने सोमवार को दरअसल प्रयोगशाला के डाटा में हेरफेर कर आंकड़े सौंपने का आरोप लगाते हुये रूस पर चार वर्षों के लंबे समय के लिये ओलंपिक और विश्व चैंपियशिप जैसे सभी बड़े अंतरराष्ट्रीय खेलों में हिस्सा लेने और उनकी मेजबानी करने या उसकी मेजबानी प्रक्रिया में हिस्सा लेने से प्रतिबंधित करने का फैसला सुनाया है।

रणजी : रेक्स सिंह ने 22 रन देकर झटके 8 विकेट

मिजोरम टीम 65 पर ऑलआउट

नई दिल्ली ए.। रणजी ट्रॉफी शुरू हो चुका है और पहले दिन ही मणिपुर के 19 वर्षीय तेज गेंदबाज रेक्स सिंह ने एक पारी 8 विकेट झटकते हुए तहलका मचा दिया। उन्होंने यह कारनामा मिजोरम की टीम के खिलाफ विंडियोकॉन अकादमी ग्राउंड कोलकाता में किया। उनके करिश्माई प्रदर्शन की बदौलत मिजेरम की पहली पारी सिर्फ 16 ओवरों में 65 रन पर सिमट गई। रेक्स ने 8 ओवर की गेंदबाजी की, जिसमें 4 ओवर मेडल रहे। उन्होंने कुल 22 रन खर्च किए और 8 विकेट झटके। दो अन्य विकेट विश्वार्जित ने लिए। दूसरी ओर, मिजोरम के लिए सबसे अधिक तरवरर कोहली ने 35 गेंदों में 8 चौके की मदद से 34 रन बनाए, जबकि लालिमांगैया ने 17 गेंदों में 4 चौके की मदद से 16 रन की पारी खेली।

7 बल्लेबाज नहीं खोल सके खाता

मणिपुर की घातक गेंदबाजी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इन दोनों के अलावा कोई भी बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा

भारत के सामने करो या मरो की चुनौती

मुंबई, । फील्डिंग और बल्लेबाजी विभाग की अपनी कमजोरियों से सबक लेते हुये भारतीय क्रिकेट टीम बुधवार को वेस्टइंडीज के खिलाफ मुंबई के वानखेडे मैदान पर तीसरे और अंतिम ट्वंटी 20 मैच में करो या मरो की स्थिति में उतरेगी जहां दोनों टीमों के लिये सीरीज दांव पर होगी।

भारत ने हैदराबाद में पहले टी-20 मैच में छह विकेट से जीत अपने नाम कर तीन मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई थी लेकिन दूसरे मैच में वेस्टइंडीज ने मेजबान टीम की खराब फील्डिंग और निचले क्रम की खराब बल्लेबाजी जैसी कमियों का बखूबी फायदा उठाते हुये तिरुवनंतपुरम में यह मैच आठ विकेट से जीत सीरीज 1-1 से बराबर कर दी।

विराट कोहली की कप्तानी वाली टीम इंडिया के लिये अब सीरीज हासिल करने के लिये विंडीज को मुंबई में बुधवार को होने वाले निर्णायक मुकाबले में हर हाल में पराजित करना होगा जबकि दो बार की ट्वंटी 20 विश्व चैंपियन वेस्टइंडीज हर हाल में इस मैच को जीत खुद को इस प्रारूप की सर्वश्रेष्ठ टीम घोषित करना चाहेगी। भारत जैसी मजबूत टीम को उसी के घर में हराना भी उसके लिये आस्ट्रेलिया में होने वाले अगले विश्वकप से पहले मनोबल बढ़ाने वाला होगा।

भारतीय टीम का दूसरे टी-20 मैच में प्रदर्शन सवालों के घेरे में रहा था और खुद कप्तान विराट ने टीम की फील्डिंग को



खराब बताते हुये कहा था कि लगातार दो मैचों में उनके खिलाड़ियों ने जिस तरह से कैच टपकाये हैं वह देखना काफी निराशाजनक है। भारत ने एक ही ओवर में दो कैच टपकाये थे जिसने मैच का रूख बदल दिया। वहीं निचले क्रम के बल्लेबाजों का प्रदर्शन भी असंतोषजनक रहा था।

ओपनिंग जोड़ी रोहित शर्मा और लोकेश राहुल इस मैच में 24 रन ही जोड़ सके जबकि चौथे नंबर पर बल्लेबाजी के लिये उतरे विराट ने भी 19 रन बनाये। टीम के ये तीनों बड़े रन स्कोरर पिछले मैच में सस्ते में आउट हुये लेकिन निचले क्रम के बल्लेबाजों में रवींद्र जडेजा और वाशिंटन सुंदर दहाई के आंकड़े को भी छू नहीं सके।

हालांकि विराट का युवा शिवम दुबे को अपने नियमित तीसरे क्रम पर उतारने का फैसला इस मैच में काम आया जिन्होंने 54 रन की बेजोड़ अर्धशतकीय पारी से टीम को 170 के लड़ने लायक स्कोर तक पहुंचाया। वहीं विकेटकीपर रिषभ पंत ने भी 33 रन की पारी खेली और नाबाद क्रीज से लौटे। लेकिन एक बार फिर साफ हो गया कि भारत अपने कुछेक बल्लेबाजों पर रन गति के लिये निर्भर रहता है। खुद विराट ने भी निचले क्रम पर मजबूत बल्लेबाजी को अहम बताया।

भारत यदि फटाफट प्रारूप की विशेषज्ञ मानी जाने वाली वेस्टइंडीज से सीरीज जीतना चाहता है तो उसके लिये मुंबई में अपनी पिछली गलतियों से

- निर्णायक तीसरे और अंतिम ट्वंटी 20 मैच आज
- इंडिया और वेस्टइंडीज टीम ने जीते हैं एक-एक मैच
- दोनों टीम के लिए प्रतिष्ठा का मैच

फील्डिंग भी टीम के लिये चिंता का विषय है। सुंदर ने पिछले मैच में लेंडल सिमंस का कैच टपकाया था जिन्होंने नाबाद 67 रन की अपनी पारी से वेस्टइंडीज को आसान जीत दिला दी थी। दूसरी ओर कुलदीप हमेशा से टीम के भरोसेमंद गेंदबाज रहे हैं, लेकिन उन्होंने आखिरी बार फरवरी में हैमिल्टन में न्यूजीलैंड के खिलाफ टी-20 मैच खेला था।

वहीं बल्लेबाजों में पंत को खुद को साबित करने का दबाव रहेगा। हालांकि विराट ने हमेशा उनका समर्थन किया है, लेकिन अपने आखिरी सात टी-20 मैचों में उनका सर्वाधिक स्कोर नाबाद 33 रन ही रहा है। उन्होंने आखिरी बार अगस्त में टी-20 में वेस्टइंडीज के खिलाफ ही अर्धशतक बनाया था। टीम में अन्य विकेटकीपर संजू सैमसन को जगह दिये जाने के बाद पंत पर अपनी जगह बरकरार रखने के लिये दबाव और बढ़ गया है।

पिछले मैच में विफल रहे रोहित भी अपने घरेलू मैदान पर बड़ी पारी खेलना चाहेंगे वहीं शिवम की कोशिश रहेगी कि वह भी अपने खेल में निरंतरता बरकरार रखें। गेंदबाजी विभाग में दीपक चाहर और भुवनेश्वर कुमार से उम्मीद रहेगी कि वे किफायती गेंदबाजी करें।

दूसरी ओर विंडीज के शीर्ष क्रम के बल्लेबाज कमाल की फार्म में हैं। लेंडल सिमंस, एविन लुईस, निकोलास पूरन और शिमरोन हेमाएर अन्य बेहतरीन स्कोरर हैं। इसके अलावा कप्तान



न्यूजीलैंड दौरे के लिए वापसी की कोशिश

नई दिल्ली ए.। पिछले कुछ समय से चोट के कारण भारतीय क्रिकेट टीम से बाहर चल रहे हरफनमौला खिलाड़ी हार्दिक पंड्या अपनी सफल सर्जरी के बाद अब रिहैबिलिटेशन की दौरे से गुजर रहे हैं। हार्दिक ने कहा कि क्रिकेट उनके खून में बसा है और वह खुद को इससे ज्यादा दूर नहीं रख सकते। उन्होंने कहा कि वह अब मैदान पर फिर से वापसी करने के लिए मानसिक रूप से फिट होना चाहते हैं। टीम से दूर रहकर खुद को हार्दिक को भी अच्छ नहीं लग रहा है। हालांकि उनका कहना है कि उन्हें अभी संयम रखने की जरूरत है।

उन्होंने यह भी कहा कि वह अपने साथ और भारतीय टीम के साथ भी अन्याय कर रहे थे। हार्दिक ने कहा, 'मैं काफी दिनों से पीठ दर्द के बावजूद खेल रहा था। मैं कोशिश कर रहा था कि मुझे सर्जरी न करानी पड़े। इसके लिए मैंने हर वह कोशिश की, जो कर सकता था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मैंने महसूस किया कि मैं अपना शतप्रतिशत प्रदर्शन नहीं दे पा रहा था। उन्होंने कहा, 'मैं अपनी उस पूरी क्षमता के साथ नहीं खेल पा रहा था, जितना खेल सकता था और इसकी वजह चोट थी। इसका मतलब यह भी था कि मैं अपने और अपनी टीम के साथ

शारीरिक और मानसिक रूप से फिट होना चाहता हूं
'पिछले चार-पांच वर्षों से खेलते हुए मैंने यह पाया है कि आप चोटिल नहीं होना चाहते हैं फिर भी आप चोटिल हो जाते हैं। यह खिलाड़ी के जीवन का एक हिस्सा है। आप यह दावा नहीं कर सकते कि चोटिल नहीं होंगे। इसलिए अब मैं मजबूत होकर वापसी करना चाहता हूं। यह पहली बार नहीं है जब हार्दिक चोट से वापसी कर रहे हैं, लेकिन इस समय वह मानसिक रूप से स्वस्थ रहना चाहते हैं। हार्दिक ने कहा यह शांत लग सकता है, लेकिन वापसी करना आसान नहीं है। हां, हम सभी को प्रेरणा मिलती है, लेकिन आपको यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि आप गलत रास्ते पर न जाएं। आप खुद से सवाल न करें। आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैं इन सब चीजों को पीछे छोड़ने की कोशिश करता हूं।

न्याय नहीं कर रहा था। इसके बाद ही मैंने सर्जरी कराने का फैसला किया।' हार्दिक ने आगे कहा, 'ईमानदारी से कहूं, तो अब मैं बहुत अच्छ महसूस कर रहा हूं। हम अच्छ काम कर रहे हैं। सर्जरी के बाद वापसी करना आसान नहीं होता। इसलिए हम पूरा एहतियात बरत रहे हैं। मैं न्यू जिलैंड सीरीज में अपने और अपनी टीम के साथ

रणजी : रेक्स सिंह ने 22 रन देकर झटके 8 विकेट

मिजोरम टीम 65 पर ऑलआउट

नई दिल्ली ए.। रणजी ट्रॉफी शुरू हो चुका है और पहले दिन ही मणिपुर के 19 वर्षीय तेज गेंदबाज रेक्स सिंह ने एक पारी 8 विकेट झटकते हुए तहलका मचा दिया। उन्होंने यह कारनामा मिजोरम की टीम के खिलाफ विंडियोकॉन अकादमी ग्राउंड कोलकाता में किया। उनके करिश्माई प्रदर्शन की बदौलत मिजेरम की पहली पारी सिर्फ 16 ओवरों में 65 रन पर सिमट गई। रेक्स ने 8 ओवर की गेंदबाजी की, जिसमें 4 ओवर मेडल रहे। उन्होंने कुल 22 रन खर्च किए और 8 विकेट झटके। दो अन्य विकेट विश्वार्जित ने लिए। दूसरी ओर, मिजोरम के लिए सबसे अधिक तरवरर कोहली ने 35 गेंदों में 8 चौके की मदद से 34 रन बनाए, जबकि लालिमांगैया ने 17 गेंदों में 4 चौके की मदद से 16 रन की पारी खेली।

7 बल्लेबाज नहीं खोल सके खाता

मणिपुर की घातक गेंदबाजी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इन दोनों के अलावा कोई भी बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा



पार नहीं कर सका। 7 बल्लेबाज तो खाता भी नहीं खोल सके। बता दें कि मणिपुर ने टॉस जीतकर पहले बोलिंग का फैसला किया था।

पिछले वर्ष झटके थे सभी 10 विकेट

उल्लेखनीय है कि रेक्स सिंह पहली बार चर्चा में तब आए थे, जब पिछले वर्ष उन्होंने कूच बिहार ट्रॉफी के एक मैच में पारी के सभी 10 विकेट ले लिए थे। रेक्स राजकुमार सिंह ने मणिपुर की ओर से खेलते हुए राजकुमार ने अरुणाचल प्रदेश की पूरी टीम को सिर्फ 11 रन देकर 10 विकेट हासिल करते हुए समेट दिया था।

ग्वाम्बू ए.। विश्व चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने के बाद से खराब दौर से जूझ रही भारतीय बैटमिंटन स्टार पीवी सिंधु को उम्मीद है कि यह बुधवार से शुरू हो रहे सत्र के आखिरी बीडब्ल्यूएफ विश्व टूर फइनल्स में वह फॉर्म में लौटेंगी। सिंधु ने अगस्त में बासेल में विश्व चैंपियनशिप जीती, लेकिन उसके बाद से वह लगातार खराब फॉर्म में हैं। ओलिंपिक सिल्वर मेडलिस्ट सिंधु जुलाई में इंडोनेशिया ओपन सुपर 750 टूर्नामेंट के फइनल में पहुंची थीं। इसके बाद कोरिया ओपन और फुजोउ ओपन में पहले दौर से बाहर हो गईं जबकि चाइना ओपन, डेनमार्क ओपन और हॉन्गकॉंग ओपन के दूसरे दौर में हारीं। बीडब्ल्यूएफ टूर ग्वाम्बू रैंकिंग में सिर्फ शीर्ष आठ खिलाड़ी ही विश्व टूर फइनल्स खेलते हैं। सिंधु इस साल के आखिर में 15वें स्थान पर होगी, लेकिन विश्व चैंपियन होने के कारण उन्हें खेलने का मौका मिलेगा।

सिंधु ने विश्व फइनल्स की तैयारी के लिये हॉन्गकॉन्ग ओपन के बाद ब्रेक लिया था। वह 2017 और 2018 में फइनल खेल चुकी है। इस बार उसे रूफ ए में चीन की चेन यू फेड, हि बिंग जियाओ और जापान की अकाने यामागुची के साथ रखा गया है। रूफ बी में ताइवान की तेड जू यिंग, थाइलैंड की रेचानोक इंतानोन और बुसानन



ओगबामरूंगफन और जापान की नोजोमी ओकुहारा हैं।

सिंधु को पहला मैच यामागुची से खेलना है जिसने इंडोनेशिया और जापान में खिताब जीते। उसके बाद कूले की चोट के कारण वह चार टूर्नामेंटों से पहले दौर में बाहर हुईं। सिंधु का इस जापानी खिलाड़ी के खिलाफ 10-6 का रेकॉर्ड है, लेकिन वह इससे पिछले दो मैच हारी है।

फ्रांसी का तख्त तैयार , 100

से फ्रांसी देने वाली स्पेशल 11 रस्सी मंगाए जाने की बात है। इन्हें जल्द मंगा लिया जाएगा। क्योंकि अगर इन चारों को फ्रांसी दी जाती है तो तिहाड़ जेल के पास जो पांच रस्सियां हैं। वह कम पड़ जाएंगी। इनमें से एक-दो रस्सी से ट्रायल भी किया जाना है।

भारतीय संविधान पर हमला

खिलाफलंडेणो को हमारे संविधान को सिस्टमेटिकली तरीके से खत्म कर रहा है। नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2019 के मुताबिक पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़ग़ानिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न के कारण 31 दिसम्बर 2014 तक भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को अवैध शरणार्थी नहीं माना जाएगा बल्कि उन्हें भारतीय नागरिकता दी जाएगी। यह विधेयक 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में भाजपा का चुनावी वादा था। भाजपा नीत राजग सरकार ने अपने पूर्ववर्ती कार्यकाल में इस विधेयक को लोकसभा में पेश किया था और वहां पारित करा लिया था। लेकिन पूर्वोत्तर राज्यों में प्रदर्शन की आशंका से उसने इसे राज्यसभा में पेश नहीं किया। पिछली लोकसभा के भंग होने के बाद विधेयक की मियाद भी खत्म हो गयी थी।

जंजीरों से बांधकर युवक को

फंसी हुई मिली है। स्कूल के सीसीटीवी फुटेज लिए जा रहे हैं। घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि युवक की उम्र 24-25 साल है। आरोपी स्कूल की बाउंड्री फांदकर अंदर आए हैं। कितने आरोपी हैं, अभी नहीं कहा जा सकता। युवक की हत्या के बाद लाश को जलाया गया है। सुबह मंत्री ने कहा कि शाम तक पूरे मामले का खुलासा हो जाएगा। यद्यपि शाम तक पुलिस जांच में ही उलझी रही। पुलिस ने पंचशील नगर से करीब चार दिन से लापता युवक अनिल के परिजनों को मौके पर बुलाया है। हालांकि परिजन को अभी लाश नहीं दिखाई गई है। पुलिस के अनुसार, पंचशील नगर के सरदार पटेल स्कूल के भीतर मंगलवार सुबह एक युवक का जंजीरों से बंधा जला हुआ शव मिला। यह शव स्कूल के भंडार कक्ष के करीब मिला है। यह युवक कौन है, इसका पता नहीं चल पाया है। स्कूल में शव होने की जानकारी मिलते ही पुलिस उममहानिरीक्षक इरशाद वली सहित अन्य पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर उसे अस्पताल भेज दिया। जानकारी मिलने के बाद राज्य के विधि मंत्री शर्मा भी सरदार पटेल स्कूल पहुंचे। उन्होंने

घटनास्थल का जायजा लेने के बाद कहा कि युवक का शव मिला है, जो जंजीरों से बंधा हुआ और जला हुआ है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। युवक की मौत की वजह का जल्द ही खुलासा किया जाएगा। आशंका इस बात की जाई जा रही है कि युवक की जलाकर हत्या की गई है। सवाल उठ रहा है कि वह स्कूल के भीतर कैसे पहुंचा। मंत्री शर्मा का कहना है कि युवक स्कूल की दीवार फांदकर अंदर आया होगा। पुलिस उममहानिरीक्षक वली का कहना है कि युवक का शव पूरी तरह जला हुआ है। यह शव 24 से 48 घंटे पुराना लग रहा है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही वास्तविकता का खुलासा हो सकेगा।

यूरिया संकट , फिर राजनीति

यूरिया पर्याप्त है, लेकिन राज्य सरकार कालाबाजियों को फायदा

पहुंचाने कुत्रिम संकट पैदा कर रही है। अकुशल सरकार प्रबंधन भी इस संकट के लिए जिम्मेदार है. सरकार ने यूरिया वितरण की 80 फीसदी सहकारी समितियों और 20 फीसदी खाद विक्रेताओं के माध्यम से की है. कृषि विभाग के अधिकारी कहते हैं राज्य में यूरिया की कोई कमी नहीं है. कृषि विभाग के प्रमुख सचिव अजित केसरी भी कहते हैं कि यूरिया संकट जैसी कोई स्थिति नहीं है. किसानों को लगातार यह मिल रहा है. इसके विपरीत मार्केटिंग फेडरेशन(मार्कफेड) के मुताबिक राज्य को केन्द्र से 18 लाख मीट्रिक टन यूरिया की दरकार थी, लेकिन 15.40 लाख टन यूरिया स्वीकृत किया गया और 11 लाख मीट्रिक टन ही अब तक मिल पया है. इसके कारण क्राइसिस पैदा हुआ है, लेकिन हकीकत कुछ और ही बयां करती है. प्रदेश के अधिकांश अंचलों की

सहकारी समितियों तक यूरिया पहुंचा ही नहीं है. जहां पहुंचा भी है, तो कतारें इतनी लंबी हैं, कि बहुतेरे किसान खाली हाथ इस उम्मीद से लौटते हैं कि शायद कल मिल जाए, लेकिन उनका यूरिया वाला कल आता ही नहीं. पुलिस की लाठी- गाली खाते-सुनते अपनी बारी का इंतजार करते हैं, या फिर धरना-प्रदर्शन करने लगते हैं. मध्यप्रदेश के रायसेन जिले के किसानों का दर्द है कि पहले उन्हें सहकारी समितियों से किसानों को बैंक खातों के आधार उधारी में खाद मिल जाता था. इस राशि को किसान फसल आने पर ब्याज सहित चुकता कर देते थे. लेकिन इस बार एक आदेश जारी कर दिया गया कि नकद राशि जमा करने पर ही किसानों को यूरिया दिया जाएगा. लिहाजा अब मार्कफेड हो या सहकारी समितियां, सभी जगह निजी दुकानों की तरह दाम नकद देना पड़ रहे हैं.

कनाडा एथलीट ऑफ द ईयर बर्नी टेनिस स्टार बियांका

वाशिंगटन । यूएस ओपन चैंपियन बियांका आंद्रेस्क्यू पहली टेनिस खिलाड़ी बन गयी हैं जिन्हें कनाडा के प्रतिष्ठित एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया है। बियांका ने अवार्ड पर खुशी जताते हुये कहा, वाह, मैं इस पुरस्कार को पाकर बहुत खुश हूं। मेरे लिये यह विश्वास करना मुश्किल है कि मैं यह अवार्ड जीतने वाली पहली टेनिस खिलाड़ी हूं। कनाडा के लोगों के समर्थन के बिना मुझे जो सफलता मिली है वह संभव ही नहीं होती। कनाडा के शीर्ष एथलीटों को हर वर्ष देश के इस सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है और 19 साल की बियांका को वर्ष 2019 में उनके सफल प्रदर्शन के लिये इस बार सम्मानित किया गया है। उन्होंने इस वर्ष परीभा ओपन में अपना पहला डब्ल्यूटीए खिताब जीता था और टोरंटो में दूसरी बार रोजर्स कप खिताब जीता था। बियांका कनाडा की पहली खिलाड़ी हैं जिन्होंने एकल ग्रैंड स्लेम जीता है, वह यूएस ओपन में विजेता रही थीं ।

न्यूज गैलरी

स्मार्ट बस का ट्रायल रन, एक बार चार्ज करने पर 200 किमी चलेगी

भोपाल। मध्यप्रदेश के पांच बड़े शहरों में प्रदूषण की समस्या को दूर करने के लिए इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। इन बसों में पेट्रोल-डीजल का झंझट नहीं होगा, इसे बस स्टैंड पर ही चार्ज कर लिया जाएगा। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में मंगलवार को इलेक्ट्रिक बस का ट्रायल रन शुरू हुआ। महापौर आलोक शर्मा ने इस बस में बैठकर शहर का भ्रमण किया। इस बस की रफ्तार भीड़भाड़ वाले इलाके और पहाड़ी रास्ते पर टेस्ट की जाएगी। 38 सीटर बसों के हिसाब से उसकी क्षमता को भी आंका जाएगा। इन बसों के चलने से भोपाल और अधिक स्मार्ट हो जाएगा। इ-बसों के ट्रायल रन में महापौर के साथ अन्य अधिकारी भी आईएसबीटी से बस में रवाना हुए। उनके साथ तकनीकी टीम भी मौजूद थीं। बताया जाता है कि एक स्मार्ट बस की कीमत एक करोड़ रुपए के आसपास है। जबकि भोपाल में पहले चरण में करीब 100 बसें चलाया जाना प्रस्तावित है।

बाघों के बाद अब जंगली कुत्तों का शिकार, सरकार ने बैठाई जांच

भोपाल। प्रदेश में बाघों के शिकार के बाद अब जंगली कुत्तों के शिकार की घटनाओं में भी बढ़ोतरी हुई है। इसे कमलनाथ सरकार ने गंभीरता से लिया है। इसके तहत अब जंगली कुत्तों की मौत पर जांच बैठा दी गई है। जांच में यदि वन विभाग के अफसरों का दोष सिद्ध होता है, तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। वन मंत्री उमंग सिंधार ने कान्हा टाइगर रिजर्व में पाँच वन्य प्राणी जंगली कुत्तों की मृत्यु की जाँच के निर्देश दिये हैं। ये जंगली कुत्ते शनिवार को गण्ठी दल द्वारा रिजर्व के खटिया परिक्षेत्र के अरोली और खोसी बीट में मृत पाए गये थे। हिस्टोपैथॉलॉजिकल और फॉरेंसिक जाँच के लिये मृत कुत्तों का विस्तरा जबलपुर के स्कूल ऑफ वाइल्ड लाइफ फॉरेंसिक एण्ड हेल्थ और सागर की फॉरेंसिक लैब में भेजा गया है। सिंधार ने अधिकारियों से कहा कि यदि जाँच में कुत्ते किसी महामारी का शिकार होना पाये जाते हैं, तो बीमारी को फैलने से रोकने के लिये सभी एहतियाती उपाय अपनायें। उन्होंने कहा कि यह भी सुनिश्चित करें कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो। क्षेत्र संचालक एल. कृष्णमूर्ति के निर्देश पर वन्य प्राणी चिकित्सक डॉ. संदीप अग्रवाल ने उप संचालक सुचिता तिकी और सहायक संचालक सुनील कुमार सिन्हा की उपस्थिति में मृत जंगली कुत्ते का पोस्टमार्टम किया। प्रथम दृष्टया जंगली कुत्ते की मृत्यु किसी बीमारी से होना प्रतीत होती है।

मेडिकल टीचर्स का अल्टीमेटम- मांगें नहीं मानी तो 9 जनवरी को दे देंगे सामूहिक इस्तीफे
भोपाल। पूर्व में सरकार ने प्रदेश के 3300 मेडिकल टीचर्स को एक महीने के अंदर मांगों के निराकरण का आश्वासन दिया था. इसकी अवधि समाप्त हो गई, लेकिन मांगों पूरी नहीं हुई हड़ताल की चेतावनी देने पर मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन के साथ 24 नवंबर को चिकित्सा शिक्षा मंत्री और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की बैठक हुई थी. बैठक में मेडिकल टीचर्स की मांग पर सरकार ने सहमति जताई थी, लेकिन इसके बावजूद कोई भी विभागीय आदेश जारी नहीं किया गया. मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन का कहना है कि 10 सालों से मांगों को लेकर सिर्फ बैठकों का दौर चल रहा है. हर बार चुनाव के समय सरकारें दावा करती हैं कि डॉक्टरों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा, लेकिन मांगें पूरी नहीं की जाती. इससे पहले चिकित्सा शिक्षकों ने अपनी मांगों को लेकर इसी साल सितंबर में सरकार के खिलाफ आंदोलन किया था. इसमें सभी 3300 डॉक्टर शामिल हुए थे.

हर्ष यादव, मंत्री, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग, मप्र शासन की पत्रकार वार्ता

नवप्रदेश संवाददाता

भोपाल। प्रगति के प्रति प्रतिबद्ध, आधुनिक प्रदेश के प्रेरणा, मध्यप्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी ने अपने एक वर्षीय कार्यकाल में विकास के आधुनिक आयामों को जिस प्रकार रेखांकित किया है, उससे एक बात स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है कि आने वाले दशक में मध्यप्रदेश देश के विकसित राज्यों की श्रेणी में अग्रणी पक्ति में खड़ा होगा। मध्यप्रदेश उन सौभाग्यशाली प्रदेशों में है, जिसका कुल वन क्षेत्र 94.689 वर्ग किलोमीटर है, जो कि राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 30.72 प्रतिशत है अर्थात मध्यप्रदेश के पास एक समृद्ध पर्यावरणीय विरासत है। मध्यप्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी की मान्यता है कि सर्वाधिक नवकरणीय ऊर्जा के प्रयोग से हम प्रदेश की इस विरासत को और समृद्धशाली बना सकते हैं। चूंकि समूचे भारत ने यह संकल्प लिया है कि वर्ष 2030 तक बिजली उत्पादन की हमारी 40 फीसदी स्थापित क्षमता ऊर्जा के स्वच्छ स्रोतों



पर आधारित होगी, इसलिए हमारे प्रदेश को इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभाना होगी। मध्यप्रदेश निरंतर प्रयासरत रहेगा कि वह ऊर्जा उपभोग के लिए अपनी परंपरागत जीवाश्म ईंधन की निर्भरता को कम करता जाये और उसे नवकरणीय ऊर्जा में तब्दील करता जाये। बीते एक वर्ष में प्रदेश में ग्रिड कनेक्टेड परियोजनाओं में 670 मेगावाट क्षमता की वृद्धि हुई है। जिसमें 645 मेगावाट की सौर परियोजनाएं एवं 25 मेगावाट क्षमता की बायोमास परियोजनाएं स्थापित की गईं। अगले चार वर्षों में लगभग 6 हजार मेगावाट क्षमता की नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा आधारित परियोजना और

स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

रीवा परियोजना-

विश्व की सबसे बड़े स्तर की 750 मेगावाट की रीवा परियोजना का पूर्णता का दो तिहाई कार्य पिछले एक वर्ष में किया गया है, 740 मेगावाट का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। दिसम्बर माह में 750 मेगावाट की पूर्ण क्षमता से उत्पादन प्रारंभ हो जायेगा। प्रतिदिन 99 मेगावाॅट बिजली रीवा से दिल्ली मेट्रो को दी जा रही है। दिल्ली मेट्रो रेल प्रदेश की बिजली से दौड़ रही है, यह हमारे लिए गर्व का विषय है।

हनी ट्रैप मामले में नौकरशाही की उंगुलियों पर नाच रहे कमलनाथ: विजयवर्गीय

नवप्रदेश संवाददाता

इंदौर। मध्य प्रदेश के कुख्यात हनी ट्रैप मामले में सूबे के कई आला अधिकारियों के फंसे होने की जानकारी का दावा करते हुए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने मंगलवार को मुख्यमंत्री कमलनाथ पर निशाना साधा। विजयवर्गीय ने कहा, मेरा मुख्यमंत्री कमलनाथ पर बेहद गंभीर आरोप है कि हनी ट्रैप मामले में वह नौकरशाही की उंगुलियों पर नाच रहे हैं, क्योंकि मुझे जानकारी मिली है कि इस प्रकरण में राज्य के बहुत बड़े अधिकारी भी संलिप्त हैं। हनी ट्रैप मामले की समसमीखेज खबरें छापने वाले एक स्थानीय सांध्य दैनिक के फरार मालिक और कारोबारी जितेंद्र सोनी के खिलाफ पुलिस-प्रशासन की जारी कार्रवाई की ओर इशारा करते हुए बीजेपी महासचिव ने कहा, यदि सूबे के बड़े अधिकारी हनी ट्रैप मामले में संलिप्त हैं और वे अपने आप को



बचाने के लिए उस तरह के धमाके (कार्रवाई) करें, जैसे हाल ही में इंदौर में हुए हैं, तब भी वे अधिकारी बेनकाब होने से बच नहीं पाएंगे।

तो कर देंगे बेनकाब

विजयवर्गीय ने कहा, मैं हनी ट्रैप मामले में फंसे अधिकारियों को चेतावनी दे रहा हूं कि वे बेनकाब होकर रहेंगे। अगर उन्हें प्रदेश सरकार ने बेनकाब नहीं किया, तो हम उन्हें बेनकाब कर देंगे। उन्होंने यहां सोनी के नाइट क्लब माई होम में काम करने वाले 11 साजिंदों को इस संस्थान के अन्य कर्मचारियों के साथ मानव तस्करी के मामले में गिरफ्तार किए जाने पर भी विरोध

जताया। उन्होंने कहा, मानव तस्करी जैसे गंभीर आरोप में गरीब कलाकारों को गिरफ्तार करना ज्यादा है। अगर इन कलाकारों पर लादे गये मामले वापस नहीं लिए गए, तो हम आंदोलन करेंगे।

विजयवर्गीय के आरोप झूठ

उधर, कमलनाथ के करीबी समर्थकों में गिने जाने वाले सूबे के लोक निर्माण मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने हनी ट्रैप मामले में मुख्यमंत्री को लेकर विजयवर्गीय के आरोपों को झूठा करार दिया। वर्मा ने कहा, कमलनाथ सूबे के मुख्यमंत्री बनने से पहले केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं।

पंचशील नगर में महिला पर चाकू से हमला, परिजनों ने नंद पर आरोप लगाया

नवप्रदेश संवाददाता

भोपाल। पंचशील नगर में एक विवाहिता पर बदमाश ने चाकू से हमला कर दिया। आरोपी ने महिला पर ताबड़तोड़ कई वार किए हैं। गंभीर हालत में महिला को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यहां उसकी हालत गंभीर है। पंचशीलनगर में सोमवार सुबह यह घटना उस वक सामने आई, जब यहां स्कूल में मिली युवक की लाश ममले की जांच करने के लिए पुलिस अधिकारी



मौजूद थे। मंत्री पीसी शर्मा भी थोड़ी देर के लिए यहां आए थे। महिला का इलाज कर रहे डॉक्टर का कहना है कि महिला पर 9 से ज्यादा वार चाकू से किए गए हैं। तीन से चार इंच के जखम हैं। उसकी हालत

नाजुक है और ब्लड प्रेशर भी कम हैं। ऐसा ज्यादा खून बह जाने के कारण हुआ है। हम कोशिश कर रहे हैं, संभवतः उसकी हालत में सुधार हो जाएगा। इधर, महिला की मां ने हमले का आरोप बेटी की नंद सिया पर लगाया है। महिला का कहना है कि बेटी की तलाक का मामला कोर्ट में चल रहा है। उस पर हमला बेटी की नंद सिया ने कराया है। सिया भोपाल में ही रहती है।

यूरिया संकट

पूरे प्रदेश में यूरिया की भारी किल्लत, किसान रात-रात भर लग रहे लाइन में

विदिशा में पुलिस के साए में बांटी जा रही यूरिया, पुलिसबल तैनात

सोमवार को शमशाबाद में लूट ली गई थीं यूरिया की 70 बोरियां

नवप्रदेश संवाददाता

विदिशा। जिले की शमशाबाद तहसील में सोमवार को यूरिया लूटने की घटना सामने आने के बाद विदिशा में मंगलवार को भारी पुलिसबल की मौजूदगी में यूरिया बांटी जा रही है। यहां के रामलीला मैदान स्थित वेयर हाउस पर सुबह से हजारों किसान लाइन में लगे हैं। किसानों



का कहना है कि वे कई दिन से सुबह से

आकर लाइन में लग रहे हैं, इसके बाद

भी उन्हें यूरिया नहीं मिल पा रहा है। जैसे ही लोगों को खबर लगी की आज वेयर हाउस से यूरिया दी जाएगी हजारों किसान वेयर हाउस पहुंच गए। हजारों किसानों को वेयर हाउस पर देखकर प्रशासन ने भारी पुलिसबल यहां तैनात कर दिया गया है। वेयर हाउस पर बुजुर्ग किसानों की फझीहत हो रही है। धक्का-मुक्की के चलते किसान लाइन से बाहर आ गए हैं। किसान बारेलाल ने बताया कि वे कई दिन से लाइन में लग रहे हैं, लेकिन उन्हें यूरिया नहीं मिल पा रहा है। किसान रंजन ने कहा कि युवा किसान बुजुर्ग किसानों

को लाइन से धक्का दे रहे हैं।

रविवार को लूट ली गई थी बोरियां: यूरिया नहीं मिलने से परेशान किसान उग्र होते जा रहे हैं। सोमवार को शमशाबाद में किसानों ने ट्रक से यूरिया की 70 बोरी लूट लीं। यह लूट तब हुई जब शमशाबाद के विपणन संघ के वेयर हाउस पर हमाल ट्रक से यूरिया की बोरी उतार रहे थे। जब आखिर में यूरिया की कुछ बोरी बचीं तो किसान ट्रक में चढ़ गए और बोरियां उठाकर ले गए। शमशाबाद के किसान पिछले 15 दिन से यूरिया का इंतजार कर रहे थे। इस

मामले में पवन गुप्ता ने अपने हम्मालों के साथ थाने पहुंच कर शिकायती आवेदन दिया है। सुबह रैक लगने के बाद यूरिया गंजबासौदा आया। तब देरी से आए किसानों ने अलग लाइन लगा ली। इस बात से पहले से खड़े किसान नाराज हो गए। उनका कहना था कि जो पहले आए हाउस पर हम्माल ट्रक से यूरिया की बोरी उतार रहे थे। जब आखिर में यूरिया की कुछ बोरी बचीं तो किसान ट्रक में चढ़ गए और बोरियां उठाकर ले गए। शमशाबाद के किसान पिछले 15 दिन से यूरिया का इंतजार कर रहे थे। इस

हनी ट्रैप मामला

आयकर विभाग का आरोप...दो एजेंसियां आमने-सामने एसआईटी का जवाब...

हनी ट्रैप में वित्तीय लेन-देन की जानकारी नहीं दे रही एसआईटी

जितना कैश मिला बता चुके, बाकी के लिए हाईकोर्ट जाएं

नवप्रदेश संवाददाता

भोपाल। बहुचर्चित हनी ट्रैप मामले में जानकारी साझा करने को लेकर आयकर विभाग और एसआईटी आमने-सामने आ गए हैं। आयकर विभाग की इन्वेस्टिगेशन विंग ने कहा है कि दो बार चिन्नी भेजने और कई बार मौखिक अनुरोध के बाद भी एसआईटी हनी ट्रैप में हुए



वित्तीय लेन-देन की जानकारी साझा नहीं कर रही। उधर, एसआईटी का कहना है कि अब तक जो कैश जन्त किया गया है, उसकी जानकारी आयकर विभाग को दी जा चुकी है। उन्हें ज्यादा जानकारी चाहिए तो हाईकोर्ट जाना होगा। आयकर विभाग की इन्वेस्टिगेशन विंग के डायरेक्टर

इंटेलिजेंस आलोक जौहरी ने कहा कि विंग ने सितंबर में हनी ट्रैप मामले का खुलासा होने के तुरंत बाद एसआईटी को चिन्नी लिखकर आरोपी महिलाओं को मिले पैसे की डिटेल साझा करने को कहा था। इसके बाद नवंबर माह में दूसरी बार एसआईटी को चिन्नी लिखी गई, लेकिन उन्हें कोई जानकारी नहीं दी

गई। जौहरी ने कहा कि मीडिया खबरों के आधार पर स्वतन्त्र संज्ञान लेते हुए विभाग अपने स्तर पर इसकी छानबीन नहीं कर सकता। उसे इस मामले में जांच के लिए कुछ पुख्ता दस्तावेज चाहिए, जो उन्हें अब तक नहीं मिले हैं। आरोपी श्वेता विजय जैन के आईसीआईसीआई बैंक स्थित लॉकर से 47 लाख रुपए की नकदी मिली थी। यह लॉकर एसआईटी ने ही खोले थे। वह आयकर विभाग की टीम साथ नहीं ले गई। आरोपी मोनिका यादव की डायरी में छत्तीसगढ़ के कुछ नौकरशाहों द्वारा गोवा में हवाला के माध्यम से 2 करोड़ रुपए हनी ट्रैप गैंग को देने की बात सामने आई थी। छत्तीसगढ़ के दो नेताओं से 7 करोड़ लेने की बात भी कुछ डायरियों में दी गई थी।

खड़े ट्रक से कार टकराई; एक ही परिवार के 4 सदस्यों की मौत, 2 की हालत गंभीर

सोमवार-मंगलवार की दरम्यानी रात करीब 3 बजे हुए हादसा

भोपाल में एक कार्यक्रम में शामिल होकर वापस सागर लौट रहा था कार सवार परिवार

नवप्रदेश संवाददाता

विदिशा। शहर से करीब 40 किलोमीटर दूर हाइवे पर अटारी खेजड़ा के पास एक कार सड़क पर खड़े ट्रक से पीछे से जा टकराई। हादसे में एक ही परिवार के चार सदस्यों की मौके पर मौत हो गई। दो बच्चों की हालत गंभीर है। कार सवार परिवार भोपाल से रहली (सागर) जा रहा था। घटना सोमवार-मंगलवार की दरम्यानी रात 3 बजे की है। रहली निवासी



अनिल कुमार जैन परिवार के साथ भोपाल में एक कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। देर रात करीब एक बजे परिवार समेत रहली के लिए निकले थे। विदिशा से आगे अटारी खेजड़ा गांव के पास कार सड़क पर खड़े ट्रक से टकरा गई। हादसे में अनिल जैन, कुसुम जैन, सुनीता जैन और एक बच्चे अनुज जैन की मौत हो गई। ज्योति जैन और आस्था जैन गंभीर रूप से घायल हो गईं। उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जबलपुर जिले में चरगवां

रोड पर बिजौरी गांव के पास मंगलवार सुबह एक तेज रफ्तार यात्री बस पलट गई। 2 लोगों की मौत हो गई। करीब 25 लोग घायल हो गए। **जीप ट्रक की भिड़ंत में 15 बच्चे घायल :** रीवा में स्कूली बच्चों को लेकर स्कूल जा रही जीप की ट्रक से टक्कर हो गई। हादसे में जीप में सवार 15 से अधिक बच्चे घायल हो गए, जिनमें 2 बच्चों की हालत गंभीर है।